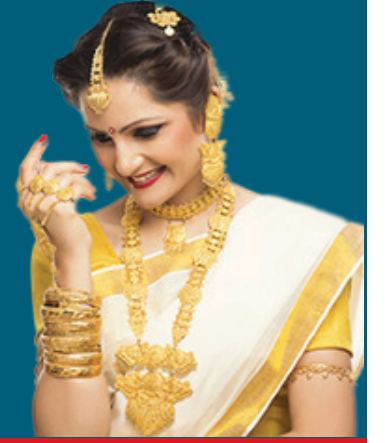




राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्रि

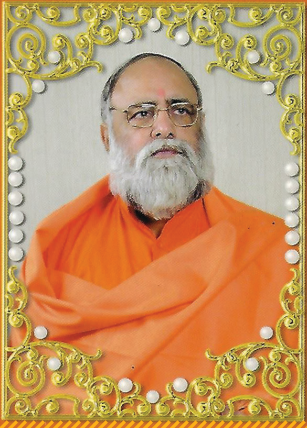
राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक



सोमवार, 20 अप्रैल 2026 • वर्ष 7 • अंक 40 • मूल्य: 5 रुपए

रिकॉर्ड कीमतों के बीच भी...

सद्गुरु वाणी



दिव्य पाठ प्रभु कृपा का वह आलोक है जिसे करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिन तपस्या या साधना की कोई जरूरत नहीं है। यह बड़ा सहज और सरल है।

विश्व भर में होने वाले प्रभु कृपा दुख निवारण समागम केवल प्रभु की कृपा से संभव होते हैं। इसका आयोजन कोई व्यक्ति नहीं करता।

परमात्मा की नजर में सभी भाई-बहन बराबर हैं। परमात्मा जाति, धर्म, देश, सम्प्रदाय से पार है। हमें सभी भाई-बहनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए।

कृपा वचन

ईश्वर सबको रास्ते देता है, फर्क बस इतना है- कोई विश्वास से चलता है, कोई सवालों में रुक जाता है।

सत्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे याद नहीं रखना पड़ता।

जब मन शांत होता है, तब ईश्वर शब्दों में नहीं, अनुभूति में बोलता है।

जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा



ट्रम्प का बड़ा दावा

क्या पाकिस्तान में होगी अमेरिका-ईरान डील या बढ़ेगा टकराव?

@ भारतश्री ब्यूरो

दुनिया की नजर इस वक्त एक ऐसे घटनाक्रम पर टिकी हुई है, जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और इजराइल जैसे बड़े देशों के बीच तेजी से बदलते हालात ने अंतरराष्ट्रीय माहौल को बेहद संवेदनशील बना दिया है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान के साथ एक अहम समझौता आज पाकिस्तान में साइन हो सकता है। उन्होंने यह बात एक समाचार चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कही। उनका कहना है कि बातचीत निर्णायक दौर में है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो डील आज ही फाइनल हो सकती है।

इससे पहले ट्रम्प ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में भी संकेत दिया था कि अमेरिका की तरफ से एक उच्चस्तरीय डेलिगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है। इस डेलिगेशन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं। ट्रम्प के मुताबिक, यह टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी है और कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएगी।

ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने जा रहा है, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि कोई गेम नहीं खेला जाएगा। यह बयान अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका इस बार बातचीत को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपनाए हुए है।

पाकिस्तान में बढ़ी कूटनीतिक हलचल

जैसे ही ट्रम्प का यह बयान सामने आया, पाकिस्तान में कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने ईरान के राजदूत से मुलाकात की। इस बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के मुद्दों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। खासतौर पर तब, जब दोनों देशों के बीच सीधा भरोसा कम हो और किसी तीसरे देश की जरूरत महसूस हो।

बातचीत पर सस्पेंस क्यों?

हालांकि ट्रम्प के दावे के बावजूद अमेरिका और ईरान



के बीच बातचीत को लेकर स्थिति साफ नहीं है। खासकर हॉरमुज में बढ़ते तनाव ने हालात को और जटिल बना दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी करके सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही उसने अमेरिका की धमकी भरी भाषा पर भी आपत्ति जताई है। ईरान का मानना है कि इस तरह के माहौल में किसी भी बातचीत की उम्मीद करना मुश्किल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में होने वाली इस संभावित बैठक पर सस्पेंस बना हुआ है। कई जानकार मानते हैं कि जब तक दोनों पक्ष अपने रुख में नरमी नहीं दिखाते, तब तक कोई ठोस नतीजा निकलना मुश्किल होगा।

क्या कई दिनों तक चल सकती है बातचीत?

एक विदेशी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत एक दिन की नहीं बल्कि कई दिनों तक चल सकती है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कोशिश यह है कि पहले एक अस्थायी समझौता यानी MoU साइन किया जाए। इस अस्थायी समझौते का मकसद होगा सीजफायर को आगे बढ़ाना और करीब 60 दिन का समय हासिल करना, ताकि एक बड़ा और स्थायी शांति समझौता तैयार किया जा सके। लेकिन यह तभी संभव है, जब ईरान इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार हो।

पिछले 24 घंटों के 5 बड़े अपडेट

इस पूरे घटनाक्रम के बीच पिछले 24 घंटों में कई अहम घटनाएँ हुई हैं, जिन्होंने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। ईरान ने हरमुज में दो भारतीय जहाजों पर फायरिंग की। इसके साथ ही 14 जहाजों को रोका गया, जिनमें से

13 को बाद में वापस भेज दिया गया। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया और विरोध दर्ज कराया। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस रणनीतिक जलमार्ग को दोबारा बंद कर दिया। इसका असर सीधे तौर पर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल नहीं होगा। उसने इसके पीछे अमेरिकी नीतियों और नाकेबंदी को जिम्मेदार ठहराया है। तनाव बढ़ने का असर बाजार पर भी साफ दिखा। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क बेंड क्रूड की कीमत करीब 6.5% बढ़कर 96.27 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। ट्रम्प ने ईरान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि यह शांति समझौते का आखिरी मौका है। उन्होंने यह भी कहा कि वह बराक ओबामा की तरह गलती नहीं दोहराएंगे।

मिशन अभी बाकी

इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल भी एक अहम खिलाड़ी बना हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ उनका सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। यरुशलम में एक मेमोरियल डे कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने संघर्ष में बढ़त जरूर हासिल की है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। उनका कहना है कि इजराइल का मिशन जारी रहेगा और वह अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि दुनिया इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को समझती है और अमेरिका के साथ मिलकर वह क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है।



राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्रो

विज्ञापन

02

सोमवार, 20 अप्रैल 2026



MN DIVINE

ORDER ALL TYPES OF :



- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.



NOW GET AT YOUR HOME ON

MNDIVINE.COM



ORDER NOW



<https://mndivine.com/>

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)



केजरीवाल को झटका

आबकारी केस में जज हटाने की मांग खारिज, कोर्ट ने कहा सिर्फ आरोप काफी नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिक्जुल याचिका खारिज करते हुए कहा कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है, और केवल आशंका के आधार पर जज को सुनवाई से अलग नहीं किया जा सकता।



@ अभिषेक चौबे

दिल्ली में चर्चित आबकारी नीति मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और अन्य आरोपियों द्वारा दायर रिक्जुल याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के जरिए मांग की गई थी कि इस मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को इस केस से अलग कर दिया जाए। अदालत ने इस मांग को आधारहीन बताते हुए साफ कर दिया कि केवल आशंकाओं और धारणाओं के आधार पर किसी जज को मामले से हटाया नहीं जा सकता।

व्याथा पूरा मामला

दरअसल, आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य पक्षकारों ने अदालत से अनुरोध किया था कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस केस की सुनवाई न करें। उनका कहना था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, जिनसे निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी आधार पर उन्होंने रिक्जुल याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे, लेकिन कोर्ट ने अंततः यह स्पष्ट कर दिया कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है।

अदालत ने विस्तार से मामले को सुना

सुनवाई के दौरान अदालत ने केजरीवाल की उस दलील पर विस्तार से टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ नेताओं या केंद्रीय मंत्रियों द्वारा दिए गए बयान इस मामले को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीतिक बयानबाजी पर अदालत का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीति में इस तरह के बयान आम बात हैं। जब दो राजनीतिक दल आमने-सामने होते हैं, तो आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि खुद केजरीवाल भी एक सक्रिय राजनेता हैं और वे इस राजनीतिक माहौल को अच्छी तरह समझते हैं। अदालत के अनुसार, केवल इस



अदालत का साफ संदेश, शक नहीं, सबूत चाहिए राजनीति के बयानों से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती बार-बैंच रिश्ते पर सवाल उठाना आसान नहीं जज की निष्पक्षता पर हमला, कोर्ट ने माना कल्पना आधारित

आधार पर कि किसी नेता ने कोई बयान दिया है, जज को हटाने की मांग करना पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। यह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है।

बार और बैंच के रिश्ते पर टिप्पणी

कोर्ट ने अपने फैसले में बार (वकील) और बैंच (जज) के रिश्ते पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि कोई भी पक्षकार इस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। अगर इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार किया जाने लगे, तो इससे न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। जज ने स्पष्ट किया कि अदालत केवल तथ्यों और कानून के आधार पर फैसले देती है। किसी भी बाहरी बयान या राजनीतिक माहौल का असर न्यायिक निर्णय पर नहीं पड़ता।

संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर उठे सवाल

रिक्जुल याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा कुछ अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं, जिससे उनके राजनीतिक झुकाव पर सवाल उठ सकता है। इस पर जज ने विस्तार से जवाब देते हुए कहा कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-राजनीतिक थे। इनमें कानूनी विषयों पर चर्चा होती है और जजों को विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित किया

जाता है। उन्होंने कहा कि देश में पहले भी कई जज ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। केवल किसी कार्यक्रम में शामिल होने के आधार पर यह मान लेना कि जज पक्षपाती हो गए हैं, पूरी तरह गलत और अनुचित है। जज ने यह भी कहा कि अदालत नियमित रूप से विभिन्न संस्थानों जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल और अन्य मंचों के कार्यक्रमों में भाग लेती रहती है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल कानूनी और सामाजिक संवाद को बढ़ावा देना होता है।

निष्पक्षता पर अदालत का रुख

जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि किसी भी न्यायाधीश की निष्पक्षता एक सामान्य धारणा होती है, जिसे बिना ठोस सबूत के खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई पक्षकार यह चाहता है कि जज खुद को मामले से अलग कर लें, तो उसे मजबूत और ठोस आधार प्रस्तुत करना होगा। केवल शक या व्यक्तिगत धारणा इस मांग के लिए पर्याप्त नहीं होती। अदालत ने यह भी कहा कि अगर केवल आरोपों के आधार पर जजों को हटाया जाने लगे, तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा पैदा हो जाएगा।

परिवार को लेकर लगाए गए आरोप

इस मामले में एक और गंभीर आरोप यह लगाया गया था कि जज के कुछ रिश्तेदार इस केस से जुड़े हो सकते

दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद को राहत नहीं

दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने जमानत से इनकार करने के अपने 5 जनवरी 2026 के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए फैसले की समीक्षा के लिए कोई ठोस आधार नहीं पाया गया। उमर खालिद ने इस मामले में जमानत न मिलने के फैसले को चुनौती देते हुए समीक्षा याचिका दायर की थी।

प्रधानमंत्री ने कहा महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूँ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात 8.30 से 9 बजे, 30 मिनट तक देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 'महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया। मैं सभी माताओं-बहनों से माफी मांगता हूँ। IPM ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, 'मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है। जब कुछ लोगों के लिए दलित देशहित से बढ़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। IPM ने आगे कहा- कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूणहत्या के गुनहवार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। नारी शक्ति के अपराधी हैं। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी।

सुभाषचंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने और आजाद हिंद फौज को भारत की आजादी का श्रेय देने की मांग वाली PIL खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को न सुधरने वाला बताया और सख्त टिप्पणी की। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागवी की बैंच ने याचिकाकर्ता पिनकपानी मोहंती को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि वह पहलभी इसी तरह की याचिका दाखिल कर चुके हैं और अब अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो याचिकाकर्ता के सुप्रीम कोर्ट में आने पर भी रोक लगाई जा सकती है। साथ ही रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि भविष्य में उनकी कोई PIL मंजूर न की जाए।

हैं। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह गलत है। सीबीआई ने भी अदालत को स्पष्ट रूप से बताया कि जज के किसी भी रिश्तेदार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। न तो उन्होंने किसी अदालत में पेशी की है और न ही वे इस केस से जुड़े किसी भी तरीके से शामिल हैं।

क्यों शादी अब सबसे बड़ा इमोशनल और फाइनेंशियल रिस्क बनती जा रही है?

NFHS और NCRB जैसे डेटा दिखाते हैं कि शादी के बाद मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा और रिश्तों में असंतोष के मामले लगातार बढ़ रहे हैं

@ सौम्या चौबे

कभी शादी को जीवन का सबसे खूबसूरत पड़ाव माना जाता था। घर वाले कहते थे अब जिंदगी सेट हो जाएगी, दोस्त कहते थे अब असली जिंदगी शुरू होगी और समाज मानता था कि शादी ही एक स्थिर और सुरक्षित जीवन का आधार है। लेकिन आज तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। अब वही शादी, जो कभी सुकून और साथ का प्रतीक थी, कई लोगों के लिए तनाव, दबाव और कभी-कभी डर का कारण बनती जा रही है। आज के समय में शादी को लेकर लोगों की सोच पहले जैसी नहीं रही। पहले जहां शादी जरूरी मानी जाती थी, वहीं अब लोग इसे चॉइस की तरह देखने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बदलती जिंदगी, बढ़ती अपेक्षाएं और रिश्तों में आ रही जटिलता।

शादी के बाद मानसिक स्वास्थ्य है सबसे बड़ी चिंता

एक मनोवैज्ञानिक सर्वे में बताया गया कि शादी के बाद लोगों में मानसिक तनाव और डिप्रेशन के लक्षण बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर शादी खराब है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि शादी के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, यह मान लेना अब सही नहीं है। डिप्रेशन के लक्षण जैसे-हर समय उदासी महसूस होना, किसी काम में मन न लगना, नींद पूरी न होना, थकान बनी रहना और भविष्य को लेकर उम्मीद कम हो जाना-ये सब अब आम होते जा रहे हैं। खासकर महिलाओं के मामले में ये लक्षण थोड़ा ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। जिम्मेदारियों का अचानक बढ़ जाना, खुद के लिए समय का न मिलना, और सबसे बड़ी बात, रिश्ते में संतुलन का बिगड़ना।

रिश्तों में हिंसा है एक कड़वा सच

आज भी शादीशुदा जीवन का एक स्याह पक्ष है, जिसके बारे में खुलकर बात कम होती है घरेलू हिंसा। आंकड़े बताते हैं कि एक बड़ी संख्या में महिलाएं अपने ही घर में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा का सामना करती हैं। लेकिन यह समस्या सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। धीरे-धीरे यह भी सामने आ रहा है कि पुरुष भी कई मामलों में मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना झेल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पुरुष अक्सर इसे खुलकर कह नहीं पाते, क्योंकि समाज उन्हें मजबूत होने की छवि में देखता है।

क्या सच में लड़कियां ओवर डिमांडिंग हो गई हैं?

पिछले कुछ सालों में एक बड़ा बदलाव आया है-औरतों की सोच में। अब महिलाएं सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं। वे अपने लिए सम्मान, बराबरी, भावनात्मक सपोर्ट और फैसलों में हिस्सेदारी चाहती हैं। यह मांग गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल जायज



हर 3 में से 1 शादीशुदा महिला आज भी किसी न किसी रूप में हिंसा झेल रही है।

हर 2 में से 1 शादीशुदा व्यक्ति किसी स्तर पर रिश्ते में ईमानदार नहीं है।

शादी के बाद डिप्रेशन के लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर महिलाओं में।

बदलती लाइफस्टाइल और खर्चों ने शादी को इमोशनल के साथ-साथ फाइनेंशियल चुनौती भी बना दिया है।

है। लेकिन समस्या तब होती है जब इस बदलाव को समझने के बजाय लोग इसे ओवर डिमांडिंग कहकर खारिज कर देते हैं। दरअसल, यह कोई ज्यादा मांग नहीं है, बल्कि एक सामान्य और स्वस्थ रिश्ते की जरूरत है। लेकिन जब दोनों पार्टनर एक-दूसरे की अपेक्षाओं को समझ नहीं पाते, तो टकराव शुरू हो जाता है।

कितना मेटर करता है पैसा?

आज के समय में जिंदगी पहले से ज्यादा महंगी हो गई है। घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, लाइफस्टाइल-सब कुछ महंगा होता जा रहा है। ऐसे में अगर एक ही व्यक्ति कमाने वाला हो, तो उस पर बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव आ जाता है। यही वजह है कि अब ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दोनों पार्टनर काम करें। लेकिन इसके साथ ही एक और चुनौती आती है-काम और घर के बीच संतुलन बनाना। अगर यह संतुलन सही से नहीं बन पाता, तो तनाव बढ़ता है और इसका असर सीधे रिश्ते पर पड़ता है।

एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशन तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं?

आज एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है-रिश्तों में भरोसे की कमी। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स यानी शादी के बाहर संबंध अब पहले से ज्यादा आम होते जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स यह संकेत देती हैं कि बड़ी संख्या में शादीशुदा लोग किसी न किसी स्तर पर अपने पार्टनर के साथ ईमानदार नहीं हैं। यह सिर्फ शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक दूरी भी इसका एक बड़ा कारण है। जब किसी रिश्ते में बातचीत कम हो जाती है, समझ कम हो जाती है और एक-दूसरे के लिए समय नहीं

बचता, तो लोग बाहर सहारा ढूंढने लगते हैं। यही चीज रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है।

क्या शादी का कॉन्सेप्ट बदल रहा है?

दुनिया के कई देशों में तलाक की दर तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, खासकर शहरों में। तलाक के पीछे कई कारण होते हैं। असंतोष, झगड़े, भरोसे की कमी, आर्थिक तनाव और सबसे बड़ा कारण, एक-दूसरे को न समझ पाना। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि तलाक हमेशा असफलता नहीं होता। कई बार यह एक गलत रिश्ते से बाहर निकलने का साहस भी होता है। आज के समय में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शादी का पारंपरिक कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे बदल रहा है। पहले जहां शादी को "जीवनभर का बंधन" माना जाता था, अब लोग इसे पार्टनरशिप की तरह देखने लगे हैं। अब लोग यह सोचते हैं कि अगर रिश्ता उन्हें खुश नहीं रख पा रहा, तो उसे निभाने का कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि अब "लिव-इन रिलेशनशिप" या बिना शादी के साथ रहने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। लोग अब अपनी खुशी को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं।

क्या सिंगल रहना गलत है?

पहले समाज में यह धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करता, तो उसके जीवन में कुछ कमी है। लेकिन अब यह सोच भी बदल रही है। आज कई लोग यह मानते हैं कि अगर वे बिना शादी के खुश हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति की खुशी का तरीका अलग होता है, और उसे वही चुनने का अधिकार होना चाहिए। सिंगल

रहना अब असामान्य नहीं माना जाता, बल्कि यह भी एक वैध जीवन शैली बन चुकी है।

समस्या शादी में है या हमारे नजरिए में?

अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या समस्या शादी में है, या हमारे उसे देखने के तरीके में? सच यह है कि शादी खुद में न तो अच्छी है और न ही बुरी। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि दो लोग उसे कैसे निभाते हैं। अगर रिश्ते में बातचीत खुलकर हो, एक-दूसरे का सम्मान हो, जिम्मेदारियां बराबर बांटी जाएं और सबसे जरूरी, एक-दूसरे को समझने की कोशिश हो तो शादी आज भी एक खूबसूरत अनुभव हो सकती है। लेकिन अगर इन चीजों की कमी हो, तो वही रिश्ता बोझ बन जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम शादी को एक "सोशल प्रेशर" के बजाय एक "पर्सनल चॉइस" की तरह देखें।

हमें यह समझना होगा कि हर किसी के लिए शादी जरूरी नहीं है और जो शादी करना चाहते हैं, उन्हें इसे समझदारी और तैयारी के साथ करना चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और ईमानदारी भी जरूरी है। शादी अब पहले जैसी सरल नहीं रही, लेकिन यह पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है। यह बस बदल रही है। समय के साथ, लोगों की सोच के साथ और समाज के ढांचे के साथ। अगर आप शादीशुदा हैं, तो जरूरी है कि आप अपने रिश्ते को समय दें, उसे समझें और बेहतर बनाने की कोशिश करें। और अगर आप सिंगल हैं, तो यह भी बिल्कुल ठीक है। खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। चाहे वह शादी में मिले या बिना शादी के।

महिला आरक्षण बिल का गिरना: बीजेपी की चाल और विपक्ष की सच्चाई

महिला आरक्षण बिल के जरिए बीजेपी कुछ खास समीकरण साधने की कोशिश कर रही थी। असल में 2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पहले से कानून बन चुका है लेकिन उसका असली अमल जनगणना और परिसीमन के बाद 2029 या उसके बाद ही हो सकता है। अब अप्रैल 2026 में संसद के खास सत्र में सरकार ने 131वां संविधान संशोधन बिल लाकर कोशिश की कि 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएं और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत 2029 से लागू हो जाए। इसमें उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सीटें ज्यादा बढ़ने वाली थीं जहां बीजेपी की पकड़ पहले से मजबूत है। दक्षिण के राज्यों में आबादी कम बढ़ी है इसलिए उनकी सीटें कम रहतीं। बीजेपी का मकसद था कि महिलाओं को सशक्त दिखाकर उनका वोट हासिल करे और साथ ही अपनी राजनीतिक ताकत भी बढ़ाए। पार्टी जानती थी कि महिलाएं अब राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं इसलिए यह बिल उनके लिए अच्छा मैसेज बन सकता था। लेकिन विपक्ष ने इसे सिर्फ महिलाओं का बिल नहीं बल्कि बीजेपी का परिसीमन वाला खेल बताया। अमित शाह ने सदन में कहा कि यह नारी शक्ति का बिल है न कि राजनीतिक। फिर भी बीजेपी को पता था कि अगर बिल पास हो जाता तो 2029 के चुनाव में उनका फायदा होता। बिल गिरने के बाद भी बीजेपी ने इसे हार नहीं माना बल्कि विपक्ष को महिलाओं का दुश्मन बताकर देशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करके कहा कि रुकावटें आएंगी लेकिन नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। कुल मिलाकर बीजेपी आरक्षण को बहाने के रूप में इस्तेमाल करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती थी और विपक्ष को घेरना चाहती थी।

बिल गिरने से बीजेपी का मनोबल और भविष्य पर क्या असर?

लोकसभा में बिल गिरने के बाद बीजेपी का मनोबल कम होने की बजाय और बढ़ गया है। 17 अप्रैल 2026 को वोटिंग में 298 सांसद पक्ष में और 230 विपक्ष में थे लेकिन दो तिहाई बहुमत नहीं मिला इसलिए बिल गिर गया। यह पहली बार था जब मोदी सरकार का कोई संवैधानिक संशोधन पास नहीं हुआ। लेकिन पार्टी ने इसे हार नहीं बल्कि मौका बनाया। अब बीजेपी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ धोखा किया। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बोले कि विपक्ष ने आधी आबादी का अपमान किया। पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर हमला बोलकर कहा कि हम रुकावटें हटाकर रहेंगे। इस घटना से बीजेपी का भविष्य और मजबूत दिख रहा है क्योंकि 2029 के चुनाव में यह मुद्दा उनके पक्ष में काम करेगा। महिलाओं के बीच यह संदेश जाएगा कि बीजेपी ने कोशिश की लेकिन विपक्ष ने रोका। पार्टी पहले से ही महिलाओं के बीच लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रही थी जैसे महिला सांसदों को आगे बढ़ाना। बिल गिरने के बाद भी 2023 वाला कानून लागू हो चुका है भले ही अमल बाद में हो। इसलिए बीजेपी कह सकती है कि हमने अपना काम किया। मनोबल पर कोई नकारात्मक

बीजेपी ने आरक्षण के बहाने क्या समीकरण साधा?



असर नहीं पड़ा बल्कि पार्टी और एकजुट हुई है। भविष्य में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर लगातार हमला करेगी और महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाने की रणनीति चलेगी। जानकार मानते हैं कि यह घटना बीजेपी के लिए राजनीतिक लाभ का सौदा साबित हो सकती है।

विपक्ष के तर्कों में कितनी ठकीकत है?

विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए कई तर्क दिए और उनमें काफी हकीकत भी है। कांग्रेस, सपा, डीएमके और इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि यह बिल महिलाओं का नहीं बल्कि परिसीमन का है। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि असली आरक्षण अभी लागू करो 543 सीटों पर ही 33 प्रतिशत दो। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उत्तर की ज्यादा आबादी वाले राज्यों में सीटें बढ़ाकर अपना फायदा चाहती है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि विपक्ष ने परिसीमन बिल गिराया जो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। विपक्ष की एक और मांग थी कि ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग आरक्षण भी हो। अखिलेश यादव ने पूछा कि बीजेपी शासित राज्यों में कितनी महिला मुख्यमंत्री हैं। इन तर्कों में हकीकत यह है कि परिसीमन से उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। 2011 की जनगणना आधार बनाने से भी विवाद होता है क्योंकि नई जनगणना 2027 के बाद होनी है। विपक्ष कहता है कि बीजेपी महिलाओं के नाम पर अपना राजनीतिक गणित साध रही है। लेकिन

विपक्ष पर भी सवाल है कि 2023 में जब बिल पास हुआ था तब उन्होंने समर्थन किया था लेकिन अब अचानक विरोध क्यों। फिर भी उनके तर्क में यह सच है कि बिना परिसीमन के तुरंत आरक्षण लागू किया जा सकता था। विपक्ष ने बिल को राष्ट्र विरोधी भी बताया लेकिन बीजेपी ने इसे महिलाओं का अपमान कहा। कुल मिलाकर विपक्ष के तर्कों में आधी हकीकत है क्योंकि परिसीमन जरूर राजनीतिक है लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने का वादा भी पूरा करना चाहिए।

राजनीतिक समीकरण और महिलाओं का भविष्य

इस बिल के गिरने से पूरे देश की राजनीति का समीकरण बदल सकता है। बीजेपी अब विपक्ष को महिलाओं विरोधी बताकर अपना अभियान चला रही है। प्रदर्शनों में महिला सांसदें आगे हैं जो संदेश दे रहा है कि बीजेपी महिलाओं के साथ है। विपक्ष की एकता दिखी लेकिन उन्हें भी महिलाओं के वोट का नुकसान हो सकता है। महिलाओं का भविष्य अभी अनिश्चित है क्योंकि 2023 का कानून लागू हो चुका है लेकिन असली आरक्षण 2029 या 2034 तक टल सकता है। अगर नई जनगणना जल्दी होती है तो परिसीमन तेज हो सकता है। लेकिन अभी विपक्ष और सत्ता पक्ष में बहस चल रही है। कई महिला संगठन कह रहे हैं कि राजनीति महिलाओं को बहाने बना रही है। इस घटना से साफ है कि आरक्षण

सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई भी है। बीजेपी को फायदा यह कि वे कह सकेंगी हमने प्रयास किया। विपक्ष को अब अपनी छवि सुधारनी होगी। कुल मिलाकर यह बिल गिरना छोटी हार लेकिन बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा बन गया है। महिलाओं को उम्मीद है कि जल्द ही उनका हक मिले चाहे किसी भी पक्ष से। देश की राजनीति अब इस मुद्दे पर केंद्रित हो गई है।

आगे का रास्ता: संतुलित नजरिया जरूरी

अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। बीजेपी और विपक्ष दोनों को समझना चाहिए कि महिलाओं का आरक्षण राजनीतिक खेल नहीं बल्कि जरूरत है। बिल गिरने के बाद भी सरकार कह रही है कि मूल कानून बरकरार है। विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए ताकि जल्द परिसीमन हो और आरक्षण लागू हो। दोनों पक्षों में संतुलन बनाना जरूरी है। बीजेपी को विपक्ष को महिलाओं विरोधी कहकर नहीं बल्कि बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। विपक्ष को भी सिर्फ विरोध नहीं बल्कि ठोस सुझाव देना चाहिए जैसे ओबीसी आरक्षण का प्रावधान। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। इस घटना से साफ है कि राजनीति में समीकरण साधना आसान नहीं। लेकिन अगर दोनों पक्ष मिलकर काम करें तो महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। अंत में यह कहना गलत नहीं कि बिल गिरना कोई अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। सबको मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए।

बदलते भारत में विपक्ष की रणनीति पर सवाल

भारत के वर्तमान राजनीतिक वातावरण को देखते हुए विपक्ष को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि अब भारत के हिंदुओं से विपक्ष को कोई उम्मीद नहीं है धीरे-धीरे पूरा हिंदू समाज एकजुट होता जा रहा है। अब तो कई कम्युनिस्ट हिंदू भी धीरे-धीरे कुछ अलग भाषा बोलने लगे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने अपनी सारी उम्मीदें मुसलमान और ईसाइयों के लिए आरक्षित कर दी हैं। वह इस बदलाव में विदेशी मुसलमान को भी अपने साथ जोड़कर देखना चाहते हैं क्योंकि भारत के विपक्षी दलों को ऐसा अंदाज हो गया है की विदेशी हिंदू भी भारत के हिंदुओं के साथ खड़े हो जाएंगे इसलिए मजबूरी समझ कर विपक्ष हिंदू मुसलमान का विभाजन कर रहा है। अब भारतीय राजनीति में विपक्ष को ऐसा अंदाज दिख रहा है कि पूरा उत्तर भारत विपक्षियों को साफ कर रहा है। उत्तर भारत से अब कांग्रेस पार्टी तथा अन्य विपक्षी दल पूरी तरह उम्मीद खो चुके हैं इसलिए अब विपक्ष दक्षिण भारत पर ही पूरी ताकत लगा रहा है। कांग्रेस पार्टी तथा अन्य विपक्षी दल अब उत्तर दक्षिण का विभाजन करना चाहते हैं। इसी विभाजन की कड़ी में कल का महिला सशक्तिकरण बिल भी मेंट चढ़ गया क्योंकि विपक्ष किसी भी परिस्थिति में अब दक्षिण भारत को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता। मैं मानता हूँ कि यह विपक्ष की एक मजबूरी है लेकिन यह देश के लिए बहुत घातक है कि भारतीय राजनीति हिंदू मुसलमान उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजित हो और विपक्ष इस आधार पर राजनीति करें। हमें विपक्ष की खुलकर निंदा करनी चाहिए।

बजरंग गुनि

महिला आरक्षण पर सरकार का स्पष्टीकरण

@ अनुराग पाठक

देश की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में है। भारत सरकार ने हाल ही में 14 सवालों वाला एक विस्तृत FAQ जारी कर यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लेकर उसकी मंशा क्या है और विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह स्पष्टीकरण वास्तव में भ्रम दूर करता है, या यह बहस को और गहरा करता है? सरकार का तर्क साफ है। वह कहती है कि अगर 2026 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन का इंतजार किया जाता, तो महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ 2029 के आम चुनाव में भी नहीं मिल पाता। इस तर्क के आधार पर सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया को अलग करते हुए महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने की कोशिश की है। पहली नजर में यह तर्क व्यावहारिक लगता है, क्योंकि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को और टालना किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से कठिन होता।

सबसे पहले, सरकार ने जो तीन विधेयक पेश किए-संविधान (131वां संशोधन) बिल, डिजिटलमिशन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन-उनका दायरा बेहद व्यापक है। यह केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की चुनावी संरचना को भी प्रभावित करता है। लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव केवल संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रतिनिधित्व के पूरे समीकरण को बदल सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखकर उठाया गया है। 1971 में जहां देश की आबादी लगभग 54 करोड़ थी, वहीं आज यह 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ाना स्वाभाविक कदम लगता है। लेकिन यह तर्क पूरी तरह निर्विवाद नहीं है। विपक्ष का डर यह है कि इस प्रक्रिया से कुछ राज्यों का राजनीतिक वजन बदल सकता है, भले ही सरकार 50 प्रतिशत समान वृद्धि का आश्वासन दे रही हो। दक्षिण भारतीय राज्यों को लेकर उठे सवाल भी इसी संदर्भ में अहम हैं। सरकार ने अपने FAQ में साफ किया है कि इन राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा नहीं, बल्कि थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन भारतीय राजनीति में आंकड़ों से ज्यादा भरोसा राजनीतिक अनुभव और आशंकाओं पर होता है। यही कारण है कि यह मुद्दा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू है-परिसीमन और महिला

आरक्षण के बीच का संबंध। सरकार का कहना है कि आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है, क्योंकि सीटों का पुनर्निर्धारण ही यह तय करेगा कि किन सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यह तकनीकी रूप से सही है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। उनका आरोप है कि परिसीमन को जोड़कर सरकार आरक्षण को टालने या अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रही है। सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र होती है और संसद तथा राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कुछ भी लागू नहीं हो सकता। साथ ही, 2029 तक होने वाले सभी चुनाव मौजूदा व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे। यह स्पष्टीकरण कुछ हद तक भरोसा जरूर देता है, लेकिन राजनीतिक अविश्वास की दीवार इतनी आसानी से नहीं टूटती।

जाति जनगणना को लेकर भी सरकार ने अपनी स्थिति साफ की है। उसने कहा है कि जाति आधारित डेटा संग्रह की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इसे टालने का कोई इरादा नहीं है। यह बयान महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के राजनीतिक माहौल में सामाजिक न्याय का सवाल लगातार जोर पकड़ रहा है। खासकर तब, जब विपक्ष महिला आरक्षण के भीतर OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटा की मांग कर रहा है। सरकार ने इस मांग को संविधान के आधार पर खारिज किया है। उसका कहना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यह एक संवैधानिक तर्क है, लेकिन यह राजनीतिक बहस को समाप्त नहीं करता। भारत जैसे विविध समाज में प्रतिनिधित्व का सवाल केवल कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक वास्तविकताओं से भी जुड़ा होता है।

केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग विधेयक लाना भी एक दिलचस्प पहलू है। जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग कानून लागू होते हैं, इसलिए वहां महिला आरक्षण लागू करने के लिए तकनीकी संशोधन जरूरी थे। सरकार का यह कदम प्रशासनिक दृष्टि से सही लगता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितनी जटिलताएं शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक नजरिए से देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि महिला आरक्षण केवल एक सामाजिक सुधार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह गहराई से राजनीतिक और संरचनात्मक बदलाव से जुड़ा हुआ है। सरकार इसे तेजी से लागू करना चाहती है, जबकि विपक्ष यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इसमें सामाजिक न्याय के सभी पहलू शामिल हों।

जुबानी तीर

“

नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और देश के विकास को नई दिशा मिलेगी। यह बिल महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित है।

नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)



“

हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन यह बिल अधूरा है। इसमें OBC महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बिना सामाजिक न्याय के यह कानून पूरी तरह प्रभावी नहीं होगा।

राहुल गांधी
(कांग्रेस नेता)



“

महिला आरक्षण का हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। जनगणना और परिसीमन की शर्तें जोड़कर इसे टालना ठीक नहीं है। महिलाओं को उनका अधिकार अब मिलना चाहिए, न कि भविष्य में।

ममता बनर्जी
(पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री)



चिलचिलाती धूप से बचाव

सनबर्न से राहत के आसान आयुर्वेदिक उपाय

गर्मी का मौसम आते ही सबसे ज्यादा असर हमारी त्वचा पर दिखाई देता है। तेज धूप, लू और बढ़ता तापमान त्वचा को झुलसा देता है। कई बार थोड़ी देर धूप में रहने भर से ही स्किन लाल पड़ जाती है, जलन होने लगती है और बाद में छाले या काली पड़ने की समस्या भी हो जाती है। इस स्थिति को सनबर्न कहा जाता है।

आज के समय में लोग सनस्क्रीन और केमिकल प्रोडक्ट्स का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए कई प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय बताए गए हैं, जो न सिर्फ सनबर्न से बचाते हैं बल्कि त्वचा को अंदर से पोषण भी देते हैं। यह लेख आपको आसान भाषा में बताएगा कि सनबर्न क्यों होता है और उससे बचने के आयुर्वेदिक तरीके क्या हैं।

सनबर्न क्यों होता है?

जब हमारी त्वचा लंबे समय तक सूरज की तेज किरणों, खासकर अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों के संपर्क में रहती है, तो त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचता है। इससे स्किन लाल, सूखी और संवेदनशील हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार, यह समस्या शरीर में पित्त दोष के बढ़ने से जुड़ी होती है। गर्मी के मौसम में पित्त स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, और अगर खान-पान व जीवनशैली सही न हो, तो इसका असर त्वचा पर साफ दिखाई देता है।

सनबर्न के आम लक्षण

त्वचा का लाल होना, जलन और चुभन, सूजन या छाले, स्किन का छिलना, खुजली और रूखापन। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या गंभीर भी हो सकती है।

आयुर्वेद में सनबर्न से बचाव का मूल सिद्धांत

आयुर्वेद कहता है कि शरीर को ठंडा रखना, पित्त को संतुलित करना और त्वचा को प्राकृतिक पोषण देना ही सबसे बड़ा उपाय है। इसके लिए घरेलू चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

एलोवेरा: त्वचा का प्राकृतिक हीलर

एलोवेरा को आयुर्वेद में घृतकुमारी कहा जाता है और यह सनबर्न के लिए सबसे असरदार उपायों में से एक है।

कैसे इस्तेमाल करें:

ताजा एलोवेरा जेल निकालकर सीधे प्रभावित जगह पर लगाएं। दिन में 2-3 बार लगाएं। त्वचा को ठंडक देता है जलन कम करता है। स्किन को जल्दी ठीक करता है।

चंदन: ठंडक और शांति का स्रोत

चंदन का इस्तेमाल सदियों से त्वचा को ठंडा रखने के लिए किया जाता रहा है।

कैसे इस्तेमाल करें:

चंदन पाउडर में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं और प्रभावित जगह पर लगाएं।

फायदा:

त्वचा की गर्मी कम करता है
लालपन और जलन को शांत करता है



पाठकों के सवाल

क्या आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है और आप उसका समाधान आयुर्वेद के माध्यम से जानना चाहते हैं? अब आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर अनुभवी आयुर्वेदाचार्य द्वारा दिया जाएगा और उन्हें इस पेज पर प्रकाशित किया जाएगा।

अपने सवाल हमें ईमेल करें

hi@bharatshri.com

कृपया अपने सवाल के साथ अपनी उम्र, शहर और समस्या का संक्षिप्त विवरण अवश्य लिखें, ताकि विशेषज्ञ सही सलाह दे सकें।

खीरा: तुरंत ठंडक देने वाला उपाय

खीरा शरीर और त्वचा दोनों को ठंडक देता है।

कैसे इस्तेमाल करें:

खीरे के स्लाइस काटकर सीधे त्वचा पर रखें या उसका रस लगाएं।

फायदा:

तुरंत ठंडक
सूजन और जलन में राहत

दही: त्वचा के लिए प्राकृतिक कूलिंग एजेंट

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ उसे साफ भी करता है।

कैसे इस्तेमाल करें:

ठंडी दही को हल्के हाथ से सनबर्न वाली जगह पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद धो लें।

फायदा:

त्वचा को ठंडा करता है
डेड स्किन हटाता है

नारियल तेल: स्किन को रिपेयर करने वाला

नारियल तेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं।

कैसे इस्तेमाल करें:

रात को सोने से पहले हल्का नारियल तेल लगाएं।

फायदा:

त्वचा को मॉइस्चर देता है
छिलने से बचाता है

गुलाब जल: त्वचा के लिए टॉनिक

गुलाब जल त्वचा को ताजगी और ठंडक

देता है।

कैसे इस्तेमाल करें:

रुई की मदद से दिन में 2-3 बार लगाएं।

फायदा:

स्किन को ठंडा रखता है
जलन कम करता है

आयुर्वेदिक पेय: अंदर से ठंडक जरूरी

सनबर्न सिर्फ बाहर की समस्या नहीं है, यह शरीर के अंदर की गर्मी से भी जुड़ा होता है। इसलिए ठंडे पेय लेना जरूरी है।

बेल का शरबत

नारियल पानी

सौंफ का पानी

छाछ

ये सभी पित्त को संतुलित करने में मदद करते हैं।

खान-पान का ध्यान

गर्मी में गलत खान-पान सनबर्न को और बढ़ा सकता है।

क्या न खाएं:

ज्यादा मसालेदार खाना

तला-भुना भोजन

चाय-कॉफी ज्यादा

क्या खाएं:

फल (तरबूज, खरबूजा)

हरी सब्जियां

हल्का और ताजा खाना

दिनचर्या में बदलाव

दोपहर 12 से 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें
ढीले और हल्के कपड़े पहनें
सिर और चेहरे को ढककर रखें
धूप से आने के बाद तुरंत ठंडे पानी से चेहरा धोएं

आयुर्वेदिक लेप (घरेलू फेस पैक)

एक आसान घरेलू लेप:

चंदन पाउडर

एलोवेरा जेल

गुलाब जल

इन तीनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और लगाएं। यह

सनबर्न में बहुत फायदेमंद होता है।

कब डॉक्टर के पास जाएं?

अगर सनबर्न ज्यादा गंभीर हो जाए, जैसे:

बड़े छाले पड़ जाएं

तेज बुखार आए

त्वचा में बहुत ज्यादा दर्द हो

तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

गर्मी के मौसम में सनबर्न एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। हालांकि बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके ज्यादा सुरक्षित, सस्ते और लंबे समय तक असर देने वाले होते हैं। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में इन छोटे-छोटे उपायों को अपनाते हैं, तो न सिर्फ सनबर्न से बच सकते हैं बल्कि आपकी त्वचा भी स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी। प्रकृति के पास हर समस्या का हल है, बस जरूरत है उसे सही तरीके से अपनाने की।

महात्मा चतुर्भुजदास जी का भगवद्भक्ति से ओतप्रोत दिव्य जीवन

परमभक्त का परिचय

महात्मा चतुर्भुजदास गोसाईं विठ्ठलनाथ के आठ दिग्गज कवियों में से एक थे। उन्हें कुम्भनदास जैसे महाभागवत का पुत्र होने का भगवान श्यामसुंदर की कृपा से सौभाग्य मिला था। उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में नित्य नवीन नवीन पद रच कर समर्पित किए। वे श्यामसुंदर के विरह को पल भर के लिए भी नहीं सह सकते थे। वल्लभ सम्प्रदाय में उनकी बड़ी मान्यता और प्रतिष्ठा है। जगत की वासना गृहस्थाश्रम में भी उनके मन का स्पर्श नहीं कर सकी। उनका मन तो भगवानमय था और भगवान उनके मनोमय परम प्रेमास्पद थे। उनमें भगवान के प्रति सख्य भाव का आवेश विशेष था और दास्य रस में भी उनकी प्रगाढ़ निष्ठा थी। वे भगवान राधारमण के परम कृपापात्र थे। उन्होंने श्री गोसाईं जी और श्रीनाथ जी में भेद दृष्टि नहीं की। उनका जन्म अलौकिक रूप से हुआ। भगवान की कृपा से कुम्भनदास की भक्ति कल्पलता के वे सरस फल थे। श्रीनाथ जी के श्रृंगार और विरह के पद लिखने में वे समान रूप से सफल थे। उनकी रचना उनकी भगवद्भक्ति और लीलारसानुभूति की दिव्य प्रतीक स्वीकार की जा सकती है। उनका काव्य पुष्टि भक्ति का अक्षर अनुवाद है। भगवान अपने भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए स्वयं अभिव्यक्त होते हैं और उनसे लीला करते हैं, खेलते हैं। चतुर्भुजदास भगवान के लीलारसिक भक्त थे।

अलौकिक जन्म की कथा

गोवर्धन से थोड़ी ही दूर जमुनावतो ग्राम में अष्टछाप के महान संत कवि श्री वल्लभाचार्य के परम कृपापात्र और गोसाईं विठ्ठलनाथ जी के अनन्य सेवक महात्मा कुम्भनदास निवास करते थे। उनके आठ पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र भक्त चतुर्भुजदास का जीवन भगवदीय रहस्यों और अलौकिक चमत्कारों से परिपूर्ण है। कुम्भनदास जी श्रीनाथ जी में सत्य भाव से अनुरक्त थे। वे एक दिन श्रीनाथ जी से खेल रहे थे। श्यामसुंदर ने उनको उस दिन चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और उसी दिन घर में पुत्र पैदा हुआ। कुम्भनदास जी ने गोसाईं विठ्ठलनाथ जी की कृपा से और भगवान की प्रसन्नता से नवजात का नाम चतुर्भुज दास रखा। चतुर्भुजदास सम्वत् 1575 वि. में जमुनावतो में ही पैदा हुए थे। जन्म के 41वें दिन शुद्धि स्नान होने पर कुम्भनदास ने नवजात को गोसाईं जी के समक्ष उपस्थित किया। उन्होंने निवेदन किया कि कृपानाथ नाम बताइए और चरण में ले लीजिए। कुम्भनदास की बात से चतुर्भुजदास किलकारी मार कर हंस पड़े। गोसाईं जी ने नवजात को ब्रह्मसम्बन्ध देकर चतुर्भुजदास नाम रखा। उन्होंने कुम्भनदास से कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे घर में परम भगवदीय पुत्र ने जन्म लिया है। तुम्हारा कुल पवित्र हो गया। गोसाईं जी ने चतुर्भुजदास को शरण में ले लिया।

पिता के सांनिध्य में भक्ति का विकास

कुम्भनदास जैसे परम विरक्त त्यागी और भगवद्भक्त महात्मा के सम्पर्क में उनका विकास होने लगा। वे नित्य प्रति अपने पिता के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन में आते थे



और अष्टछाप के दिग्गजों के कीर्तन और सेवा भाव ने उनके चरित्र को विशेष रूप से प्रभावित किया था। उनके सत्संग और पदगान का चतुर्भुजदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे बाल्यावस्था से ही पद रचना करने लगे तथा श्रीनाथ जी में उनकी आसक्ति नित्य निरंतर बढ़ती गयी। वे श्रीनाथ जी की गाय भी चराया करते थे। धीरे धीरे उनका मन श्रीनाथ जी की लीला से तथा कीर्तन और सेवा से जगत के प्रति अनासक्त हो उठा।

विरक्त स्वभाव और गृहस्थ जीवन

चतुर्भुजदास जी पिता कुम्भनदास की ही तरह विरक्त और निस्पृह स्वभाव के थे। प्रभु के चरणों में मन लग जाने पर जगत के प्रति उदासीनता का उदय होना तो स्वाभाविक ही है। वे बड़े सरल और निष्कपट थे। विवाह हो जाने पर भी गृहस्थाश्रम में वे अनासक्त ही रहे। उनके जीवन में अद्भुत सादगी और विचित्र सरलता का मिश्रण था। वे खेती करके जीविका चलाते थे। वे कुम्भनदास जी के सबसे छोटे पुत्र थे पर घर में परम भगवदीय भी वे ही थे। कुम्भनदास उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। उनकी कृपा से धीरे धीरे चतुर्भुजदास को नन्दनन्दन की लीला की अनुभूति होने लगी। उनका गृहस्थ जीवन उनकी भक्ति भावना के अनुरूप ही था। पिता की देखा देखी उनके साथ ही श्रीनाथ जी की सेवा में पद रचने लगे। उन्हें काव्य और संगीत की अच्छी शिक्षा पिता से ही मिल गयी। वे संस्कृत और व्रजभाषा के महान पण्डित थे। खेती बारी के काम में भी वे बड़े कुशल थे। भगवान की सेवा में लीलानुभूति और कीर्तन में कोई विघ्न न आए इस दृष्टिकोण से गृहस्थाश्रम का उन्होंने उचित ढंग से उपयोग किया। लौकिक कार्य में भी भगवद्भक्ति को महत्ता दी। उनका जीवन अलौकिक

देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे उसी प्रकार प्रभु भी उनके साथ खेले बिना स्वात्म सुख का अनुभव नहीं कर पाते थे। यद्यपि वे सर्वशक्तिमान सर्व लोकमहेश्वर हैं पर लीला के क्षेत्र में दिव्य प्रकृति और भक्तों के सर्वथा अधीन रहते हैं। श्रीनाथ जी चतुर्भुजदास के साथ नित्य खेला करते थे। प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनको धन्य करते थे। चतुर्भुजदास की पत्नी का देहान्त हो गया। सूतक लगने पर भी चतुर्भुजदास खेलने के लिए वन में अकेले बैठ कर प्रभु के आने की राह देखा करते थे और कृपामय श्यामसुंदर लीलापूर्वक सूतक में स्पर्श हो जाने के भय से उनसे थोड़ी दूर पर स्थित रह कर खेला करते थे। भगवान को सूतक नहीं लग सकता है पर प्रभु तो भक्त की यशवृद्धि के लिए ऐसा स्वांग लीला करने में परमानंद का अनुभव करते हैं। चतुर्भुजदास श्रीनाथ जी के अन्तरंग सखा थे और उनका समस्त जीवन श्यामसुंदर के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित था।

गुरु निष्ठा और पदों में लीला चित्रण

चतुर्भुजदास जी का दृढ़ विश्वास था कि गुरुकृपा और भगवद्भक्ति एक ही वस्तु है। वे महाप्रभु गोसाईं जी और उनके सात पुत्रों में बड़ी निष्ठा रखते थे। वृद्ध पिता के साथ ही अष्टछाप के कवियों में स्थान प्राप्त करना उनकी गुरुनिष्ठा और भगवद् भक्ति का प्रत्यक्ष फल है। उन्होंने अपने पदों में श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रति उनकी श्रद्धापूर्ण उक्ति है।

“श्रीवल्लभ सुजस सन्तत नित्य गाऊँ। मन क्रम वचन छिन एक न विसराऊँ।”

उन्होंने गोसाईं विठ्ठलनाथ जी के सम्बन्ध में कहा है कि श्रीवल्लभ नन्दन और नन्दनन्दन दोनों एक मन और दो रूप हैं।

“चतुर्भुज प्रभु गिरिधरन युग वपु लीला अनूप । नन्दनन्दन श्रीवल्लभनन्दन एक मन द्वे रूप।”

उनकी दृष्टि में गोसाईं विठ्ठलनाथ साक्षात् पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी ही थे।

विरह की पीड़ा और लीला प्रवेश

सम्वत् 1642 वि. में गोसाईं विठ्ठलनाथ जी का गोलोक वास हो गया। वे उनके विरह को नहीं सह सके। वे चिन्तित हो उठे कि नन्दराय का वैभव अब संसार में दिखलाने वाला दूसरा कोई नहीं रह गया है। गोसाईं जी का दर्शन फिर नहीं मिल सकेगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और कुछ समय के बाद रुद्र कुण्ड पर एक इमली के वृक्ष के नीचे उनका लीला प्रवेश हो गया। अन्त समय में उन्होंने गोसाईं जी की स्तुति का एक पद गाया और श्रीनाथ जी का दर्शन किया। निस्सन्देह चतुर्भुजदास महान भगवदीय रसिक महात्मा विरक्त गृहस्थ और भक्त संत थे।

रचनाएं

श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव से लेकर विरह तक के अनेक लीलापूर्ण और दिव्य श्रृंगारमय पदों की रचना की। चतुर्भुजदास के बालभाव पालना श्रृंगार रास लीला और विनय के पद पुष्टिमागीय कीर्तन संग्रह में संकलित हैं।

और भागवत था। श्रीनाथ जी उनके परम उपास्य थे पर वे कभी कभी गोकुल में नवनीतप्रिय का दर्शन करने जाया करते थे।

भगवान की विशेष कृपा और प्रत्यक्ष लीला

चतुर्भुजदास पर श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा रहती थी। ऐसे तो प्रभु की कृपा सब जीवों पर समान रूप से है पर विशेष भक्त पर वे अपनी विशेषता प्रकट करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। उन्हें श्रीनाथ जी की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। उनकी वाणी व्रज रस से सराबोर थी। उनकी कविता श्रीनाथ जी की सौन्दर्य माधुरी की प्रतीक थी। एक बार आधी रात के समय जमुनावतो में प्रभु की ओर विचार करते थे। जमुनावतो से श्रीनाथ जी का मन्दिर दिख पड़ता था। मन्दिर में दीप जल रहे थे। रसिक कुम्भनदास के अवसर पर श्रीनाथ जी का अनुराग थिरक उठा। भक्त कवि ने अपने पुत्र से कहा श्रीनाथ जी के मन्दिर के झरोखों से दीपक के प्रकाश का निकलना चित्रित किया।

“वे देखो वरत झरोखन दीपक हरि पौढे ऊँची चित्र सारी।”

चतुर्भुजदास जी ने इस वर्णन की सरसता से उन्मत्त होकर भगवद् लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति कर पिता को आश्चर्यचकित कर दिया। भगवान श्रीनाथ जी की परम निगूढ़ केली लीला के स्तवन में उनकी भागवती वाणी बोल उठी।

“सुन्दर वदन निहारन कारन बहुत यतन करि राखे है प्यारी।”

श्रीनाथ जी के प्रति उनकी भक्ति सिद्ध थी। प्रभु की लीला विचित्र होती है। जिस प्रकार चतुर्भुजदास प्रभु को

रिकॉर्ड कीमतों के बीच भी सोने पर अटूट भरोसा

बाजार में लौटी चमक

अक्षय तृतीया 2026 पर भारत में लगभग 18-20 टन सोने की बिक्री हुई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत पिछले वर्ष के लगभग 90,000 रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये से ऊपर पहुंच गई।

@ रिकू विश्वकर्मा

भारत में सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक है। यही वजह है कि जब भी अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर आते हैं, तो देशभर में सोने की खरीदारी एक उत्सव का रूप ले लेती है। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब आसमान छूती कीमतों के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। बल्कि, कई मामलों में तो यह उत्साह पिछले वर्षों से भी अधिक दिखाई दिया।

महंगाई बनाम आस्थामें कौन जीता?

इस साल सोने की कीमतों ने अभूतपूर्व स्तर छुआ। जहां पिछले वर्ष 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 90,000 रुपये के आसपास थी, वहीं इस बार यह बढ़कर लगभग 1.5 लाख रुपये से ऊपर पहुंच गई। सामान्य आर्थिक तर्क कहता है कि इतनी तेज महंगाई के चलते मांग में गिरावट आनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय बाजार ने एक बार फिर इस धारणा को चुनौती दी। अक्षय तृतीया के दिन देशभर के ज्वेलरी शोरूम में उमड़ी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि सोना केवल कीमतों से नहीं, बल्कि विश्वास से चलता है। ग्राहकों के लिए यह महज एक खरीदारी नहीं, बल्कि शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। यही कारण है कि बढ़ती कीमतें भी लोगों को रोक नहीं सकीं।

20 टन तक पहुंचा कारोबार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल अक्षय तृतीया पर पूरे देश में लगभग 18 से 20 टन सोने की बिक्री हुई। यह आंकड़ा न केवल मजबूत मांग को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। ज्वेलरी डोमेस्टिक के चेयरमैन राजेश रोकड़े के अनुसार, व्यापार की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, जहां सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। इसके बाद धीरे-धीरे यह रफ्तार पूरे देश में फैल गई। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दोपहर के बाद खरीदारी में तेज उछाल आया। कई शहरों में स्थिति यह रही कि दुकानदारों को देर रात तक शोरूम खुले रखने पड़े। यह दृश्य बताता है कि सोने की मांग केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में समान रूप से मजबूत है।

दक्षिण से उत्तर तक एक जैसी दीवानगी

दक्षिण भारत में सोने का सांस्कृतिक महत्व हमेशा से अधिक रहा है। इस बार भी वहीं से खरीदारी की शुरुआत हुई। सुबह-सुबह मंदिरों में पूजा के बाद लोग सीधे ज्वेलरी दुकानों की ओर बढ़े। वहीं उत्तर और पश्चिम भारत में खरीदारी का पैटर्न थोड़ा अलग दिखा। यहां दोपहर और शाम के समय भीड़ ज्यादा रही। खासतौर पर महानगरों में ऑफिस के बाद लोग परिवार के साथ शॉपिंग करने

- ▶▶ कीमतें आसमान छूएं, आस्था और निवेश दोनों ने सोने को चमकाया।
- ▶▶ दक्षिण से लेकर उत्तर तक, अक्षय तृतीया पर फैली सोने की दीवानगी।
- ▶▶ घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर से डिजिटल युग ने भी बदला सोने का खरीदारी तरीका।
- ▶▶ युवाओं की पसंद अब हल्के डिजाइन, लेकिन भरोसा अभी भी पुरानी सोने की चमक में।



पहुंचे। दिलचस्प बात यह रही कि छोटे शहरों और कस्बों में भी इस बार जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। यह संकेत है कि सोने की मांग अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही।

शगुन से शादी तक- क्या खरीद रहे हैं लोग?

इस बार खरीदारी के पैटर्न में भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिला। जहां एक ओर पारंपरिक रूप से शगुन के लिए सोने के सिक्कों की मांग बनी रही, वहीं दूसरी ओर शादी-ब्याह के लिए भारी गहनों की एडवांस बुकिंग भी बड़ी संख्या में हुई। कल्याण ज्वेलर के एजीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश कल्याणरामन के मुताबिक, इस बार ग्राहकों ने केवल छोटे-मोटे गिफ्ट आइटम तक खुद को सीमित नहीं रखा। बड़ी संख्या में लोगों ने शादी के लिए गोल्ड सेट्स और हैवी ज्वेलरी की बुकिंग करवाई। यह ट्रेंड इस बात की ओर इशारा करता है कि लोग सोने को केवल त्योहार तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे दीर्घकालिक जरूरतों से भी जोड़ते हैं।

डिजिटल युग का दिखा असर, लोगों ने घर बैठे खरीदा सोना

इस साल एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसने बाजार को नया आयाम दिया। अब सोने की खरीदारी केवल ज्वेलरी दुकानों तक सीमित नहीं रही।

इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों ने घर बैठे सोने और चांदी के सिक्के मंगवाए। यह सुविधा खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद रही, जो भीड़भाड़ से बचना चाहते थे या आखिरी समय पर खरीदारी करना चाहते थे। यह ट्रेंड बताता है कि पारंपरिक सेक्टर भी अब डिजिटल बदलाव को अपनाने लगा है। आने वाले समय में यह मॉडल और तेजी से बढ़ सकता है।

युवा बदल रहे हैं बाजार का चेहरा

सोने के बाजार में सबसे बड़ा बदलाव युवा ग्राहकों की वजह से आया है। पहले जहां ज्यादातर लोग 22 कैरेट सोने को ही प्राथमिकता देते थे, अब यह सोच बदल रही है। एक ब्रांड के मैनेजिंग डायरेक्टर कोलिन शाह के अनुसार, इस साल बिक्री में करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें बड़ी भूमिका युवा ग्राहकों की रही। अब युवा ग्राहक 9 कैरेट, 14 कैरेट और 18 कैरेट ज्वेलरी की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

खासकर डायमंड ज्वेलरी और हल्के वजन वाले डिजाइन उनकी पहली पसंद बनते जा रहे हैं। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। पहला, यह ज्वेलरी बजट में फिट बैठती है। दूसरा, यह रोजमर्रा के उपयोग के लिए अधिक सुविधाजनक है। तीसरा, यह फैशन और स्टाइल के लिहाज से भी अधिक आधुनिक है।

चांदी भी पीछे नहीं

जहां सोने की मांग मजबूत रही, वहीं चांदी ने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। चांदी के सिक्कों और सजावटी वस्तुओं की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। मध्यम वर्ग के लिए चांदी एक सस्ता और आकर्षक विकल्प बनकर उभरी है। खासतौर पर शगुन और गिफ्टिंग के लिए लोगों ने चांदी की बड़ी संख्या में खरीदा।

निवेश का नया नजरिया

आज के समय में सोने को केवल आभूषण के रूप में नहीं देखा जाता। यह एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि ने लोगों के विश्वास को और मजबूत किया है। अब ग्राहक इसे एक सुरक्षित और स्थिर निवेश के रूप में देख रहे हैं।

सोने में निवेश के कुछ प्रमुख कारण जो बताए गए वो हैं महंगाई के खिलाफ सुरक्षा, दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि, आर्थिक अनिश्चितता में स्थिरता, आसान लिक्विडिटी, यही कारण है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद लोग पीछे नहीं हट रहे।

क्या कहता है बाजार का भविष्य?

इस साल अक्षय तृतीया पर जिस तरह की मांग देखने को मिली है, उससे यह साफ है कि आने वाले महीनों में भी जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में तेजी बनी रह सकती है। फेस्टिव सीजन, शादी का सीजन और निवेश की बढ़ती जागरूकता इस मांग को और बढ़ा सकते हैं। हालांकि, एक सवाल जरूर बना हुआ है कि अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रहें, तो क्या भविष्य में मांग प्रभावित होगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है, वह बताता है कि भारतीय बाजार में सोने की पकड़ बेहद मजबूत है।

परंपरा और निवेश का संगम

अक्षय तृतीया 2026 ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत में सोने का महत्व केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है।

कीमतें चाहे जितनी बढ़ जाएं, लेकिन जब बात शुभ अवसर, परिवार और भविष्य की सुरक्षा की होती है, तो सोना आज भी सबसे भरोसेमंद विकल्प बना हुआ है।

यह साल केवल रिकॉर्ड बिक्री का नहीं, बल्कि बदलती सोच और नए ट्रेंड्स का भी संकेतक है। जहां एक ओर परंपरा कायम है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता भी तेजी से जगह बना रही है। और यही संतुलन भारतीय जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर को आने वाले समय में और मजबूत बना सकता है।

ब्रह्मस्वरूपिणी ऋतुखुशबू जी ने विद्यार्थियों को दिए जीवन, संस्कार और साधना के सूत्र

@ भारतश्री व्यूरो

भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम पब्लिक स्कूल, पटियाला में एक विशेष आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायी अवसर देखने को मिला। जब गुरुमां हरबंस कौर जी, ब्रह्मस्वरूपिणी ऋतुखुशबू जी तथा श्री जतिन शर्मा वशिष्ठ जी ने विद्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर ब्रह्मस्वरूपिणी ऋतुखुशबू जी ने विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्हें जीवन मूल्यों, अनुशासन और आध्यात्मिकता के महत्व से अवगत कराया। सबसे पहले गुरुमा जी ने गुरुदेव की ओर से सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मां दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी अच्छा कार्य करें और अपने माता-पिता तथा गुरु का नाम रोशन करें। इसके बाद ब्रह्मस्वरूपिणी ऋतुखुशबू जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी परमात्मा हमारे जीवन में आते हैं, तो वे किसी न किसी रूप में आते हैं। जैसे कि आपने गीत गाया-जब आप गाना गाते हैं, तो मां शारदा की साक्षात कृपा आप पर होती है। मां सरस्वती की कृपा के बिना स्वर नहीं आ सकते और न ही संगीत गाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नृत्य के सबसे बड़े देवता भगवान शिव हैं। जब आप नृत्य करते हैं, तो एक तरह से परमात्मा की आराधना ही करते हैं। आप भगवान शिव की उपासना कर रहे होते हैं। जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं या पूजा करते हैं, हर रूप में परमात्मा आपके साथ विद्यमान रहते हैं। जब आप पढ़ाई-लिखाई करते हैं, तब शिक्षक आपके साथ होते हैं। शिक्षक परमात्मा के ही रूप होते हैं, क्योंकि वे आपको जीवन जीने का तरीका सिखाते

हैं। पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ वे आपको यह भी सिखाते हैं कि समाज में किस प्रकार रहना और व्यवहार करना चाहिए।

मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा अपने शिक्षकों, अपने गुरु और अपने माता-पिता का सम्मान करें। अपने घर के सभी बड़े-बुजुर्गों का आदर करें। आपके माता-पिता कभी भी आपको गलत राह नहीं दिखाएंगे और न ही आपको गलत बातें सिखाएंगे। जब हम कम उम्र में होते हैं, तो कई बार हमें अपने अभिभावकों की बातें ऐसी लगती हैं मानो वे हमें रोक रहे हों। उनकी बातें कभी-कभी हमें कठोर लगती हैं और हमें लगता है कि हमें अधिक स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे अभिभावक हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनका यह संरक्षण भी परमात्मा की ही कृपा का रूप है।

जब जीवन में कभी हमें कोई चीज नहीं मिलती, या हम कुछ चाहते हैं और वह नहीं मिलता, तो हमें परमात्मा पर क्रोध आता है। हमें लगता है कि भगवान ने हमें वह चीज क्यों नहीं दी। लेकिन परमात्मा जानते हैं कि किस समय हमें क्या देना उचित है। परमात्मा, गुरु, माता-पिता और शिक्षक-सभी हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। जब वे सभी मिलकर हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा देते हैं, तभी हम जीवन के विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए समाज में जीने के योग्य बनते हैं, उसका सामना कर पाते हैं और आगे बढ़ते हैं।

फिर बच्चों को संबोधित करते हुए जतिन शर्मा वशिष्ठ जी ने कहा कि आप सभी बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ सदैव गुरु की कृपा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि हमारा पहला गुरु परमात्मा होता है। जन्म लेने के बाद हमारी पहली गुरु हमारी मां होती है। मां के बाद जब हम विद्यालय जाते हैं, तो हमारे गुरु शिक्षक और शिक्षिकाएं होती हैं। हमारे स्कूल के शिक्षक हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे बैठना है, कैसे चलना है और किस प्रकार अनुशासित रहना है। वे हमारे भीतर हिम्मत और आत्मविश्वास भी विकसित करते हैं। समाज का सामना हम किस प्रकार करेंगे, यह भी हमें शिक्षा के माध्यम से ही सिखाया जाता है। हर एक महत्वपूर्ण बात हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। हम घर की अपेक्षा अधिक समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, तो उसे बार-बार पूछना चाहिए, लेकिन उसे सीखना अवश्य चाहिए।



अश्लीलता की लहर: सिनेमा और सोशल मीडिया क्यों बदल रहे हैं समाज को?

सिनेमा और ओटीटी में बढ़ती अश्लीलता: दर्शकों का नया स्वाद

आजकल भारतीय सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता काफी तेजी से बढ़ रही है। पहले फिल्मों में कहानी, गाने और भावनाएं मुख्य होती थीं, लेकिन अब कई फिल्मों और वेब सीरीज में बोल्ड सीन, अश्लील भाषा और संवेदनशील विषयों को ज्यादा जगह दी जा रही है। इसका एक बड़ा कारण है दर्शकों का बदलता स्वाद। युवा पीढ़ी अब तेज़ मनोरंजन चाहती है और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या छोटे प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध कंटेंट इसे बढ़ावा दे रहा है। सरकार ने भी इस पर नजर रखी है। 2024 में 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को अश्लील और वल्यर कंटेंट के लिए ब्लॉक किया गया, फिर 2025 में 25 और प्लेटफॉर्म जैसे उल्लू, एएलटीटी और अन्य को बंद किया गया। 2026 की शुरुआत में भी 5 प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हुई। इसका मतलब है कि कुल 43 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई जा चुकी है। फिल्मों में भी सेंसर बोर्ड अब गाने जैसे 'सरके चुनर' या 'टॉक्सिक' फिल्म के टीजर पर आपत्ति जता रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। थिएटर और ओटीटी दोनों को दर्शक चाहिए, इसलिए कुछ निर्माता कहानी से ज्यादा सनसनीखेज सीन पर जोर देते हैं। इससे पैसा तो आता है, लेकिन समाज की पुरानी मूल्य प्रणाली प्रभावित होती है। कई लोग कहते हैं कि ये स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरी तरफ माता-पिता चिंतित हैं कि बच्चे ऐसे कंटेंट से क्या सीख रहे हैं। कुल मिलाकर, ये ट्रेंड सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक बदलाव दिखा रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल अश्लील रीलस: आसान पहुंच का नुकसान

सोशल मीडिया आज हर घर में पहुंच गया है और यहां अश्लीलता सबसे तेज फैल रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर छोटी-छोटी रीलस और वीडियो में अश्लील डांस, भाषा और इशारे इतने आम हो गए हैं कि युवा इन्हें देखकर बड़ा महसूस करते हैं। एल्गोरिदम ऐसे कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करता है क्योंकि लोग ज्यादा समय स्कॉल करते रहते हैं। एक साधारण रील लाखों व्यूज पा जाती है और क्रिएटर को पैसा मिलता है। लेकिन इसका असर गहरा है। बच्चे और किशोर आसानी से इन वीडियो तक पहुंच जाते हैं क्योंकि कोई सख्त चेक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को रोकने के लिए कानूनी खालीपन है। यहां कोई सेंसर बोर्ड नहीं बैठता, सिर्फ प्लेटफॉर्म खुद नियम बनाते हैं जो अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। नतीजा ये कि युवा पीढ़ी को गलत संदेश मिल रहा है कि अश्लीलता ही आधुनिकता है। कई मामलों में महिलाओं की गरिमा प्रभावित होती है और परिवारों में बहस बढ़ जाती है। सरकार आईटी रूल्स 2021 के तहत चेतावनी दे रही है, लेकिन लागू करना



मुश्किल है क्योंकि कंटेंट रोज नया बनता रहता है। सोशल मीडिया की आजादी अच्छी है, लेकिन बिना जिम्मेदारी के ये समाज को तोड़ भी सकती है। लोग अब सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या आने वाली पीढ़ी की सोच बदल रहा है।

समाज पर वैज्ञानिक प्रभाव: अध्ययन क्या बताते हैं

वैज्ञानिक अध्ययन साफ कहते हैं कि मीडिया में ज्यादा अश्लीलता समाज पर बुरा असर डालती है। पुराना हिक्लिन टेस्ट भी यही कहता है कि ऐसी सामग्री जो युवा दिमाग को गलत दिशा दे, वो अपराधी सोच पैदा कर सकती है। आज के रिसर्च बताते हैं कि बार-बार सेक्सुअल कंटेंट देखने से ब्रेन डेसेंसिटाइज हो जाता है, यानी सामान्य रिश्तों में रोमांच कम लगने लगता है। युवाओं में ऑब्सेक्टिविफिकेशन बढ़ता है, मतलब महिलाओं को सिर्फ शरीर के रूप में देखा जाने लगता है। भारत में कई स्टडीज दिखाती हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर ऐसे कंटेंट देखते हैं तो उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है – चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत और रिश्तों में गलत समझ बढ़ती है। कुछ रिसर्च में पाया गया कि ज्यादा एक्सपोजर से इंटरनेट एडिक्शन और भावनात्मक अनियमितता होती है। परिवारों में बातचीत कम हो जाती है और स्कूल में भी बच्चे गलत भाषा इस्तेमाल करने लगते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर सही शिक्षा और मीडिया लिटरेसी हो

तो नुकसान कम किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर स्टडीज चेतावनी देती हैं कि बिना रोक-टोक के ये समाज की नैतिकता को कमजोर कर रहा है। भारत जैसे देश में जहां परिवार की परंपरा मजबूत है, वहां ये बदलाव और भी गहरे प्रभाव डाल रहा है। वैज्ञानिक तर्क यही है कि कंटेंट सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि दिमाग को आकार देने वाली चीज है।

सेंसर बोर्ड की सक्रियता: फिल्मों पर नजर रखना

सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी आजकल काफी सक्रिय दिख रहा है। फिल्मों में अश्लील शब्द, सीन या गाने आने पर वो कट लगाने या बदलाव मांग रहा है। हाल ही में अप्रैल 2026 में 'भूत बंगला' फिल्म से कुछ अश्लील शब्द हटवाए गए। 'सरके चुनर' गाने पर हरियाणा और कर्नाटक महिला आयोग ने बोर्ड से शिकायत की। 'टॉक्सिक' फिल्म के टीजर पर भी आपत्तियां आईं। बोर्ड थिएटर रिलीज से पहले सर्टिफिकेट देता है और जरूरत पड़ने पर कट मांगता है। लेकिन ओटीटी पर ये सीमा कम है क्योंकि वहां सेल्फ रेगुलेशन है। सरकार ने बोर्ड की मदद से कई बार चेतावनी दी है।

बोर्ड के सदस्य फिल्म देखकर फैसला लेते हैं कि वो समाज के लिए ठीक है या नहीं। कई फिल्मकार कहते हैं कि बोर्ड कभी-कभी ज्यादा सख्त हो जाता है, लेकिन सरकार का कहना है कि शिकायतें बढ़ रही हैं इसलिए जरूरी है। बोर्ड की सक्रियता से कुछ हद तक थिएटर

फिल्मों में कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया और छोटे प्लेटफॉर्म पर पहुंच नहीं होती। कुल मिलाकर, बोर्ड अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन पूरा बोझ अकेले नहीं उठा सकता। ये एक संतुलन का खेल है – रचनात्मकता और समाज की सुरक्षा के बीच।

सबसे बड़ी लूपहोल: सोशल मीडिया और नियमों की कमी

सबसे बड़ी लूपहोल सोशल मीडिया में है जहां यूजर खुद कंटेंट बना लेते हैं और कोई प्री-सेंसरशिप नहीं होती। ओटीटी पर आईटी रूल्स 2021 सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, लेकिन कई प्लेटफॉर्म इसे टाल देते हैं जिसके कारण सरकार को ब्लॉक करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए कानूनी खालीपन है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब या इंस्टा पर लाखों वीडियो रोज अपलोड होते हैं और उन्हें चेक करना मुश्किल है। पाइरेसी और छोटे ऐप्स भी नियमों से बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार नई कानून बनाने की सोच रही है, लेकिन अभी तक पूरा समाधान नहीं मिला। ये लूपहोल समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि यहां पहुंच सबसे आसान है। अगर इसे बंद किया जाए तो बाकी सब कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन चुनौती ये है कि टेक्नोलॉजी तेज है और कानून पीछे। संतुलित तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है ताकि मनोरंजन बने रहे लेकिन समाज सुरक्षित भी रहे।

राहुल गांधी: हार की राह पर भी डटे रहे, लेकिन क्या भारत की राजनीति उन्हें सच में तैयार मानती है?



राहुल गांधी पिछले 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। 2004 में अमेठी से पहली बार जीते थे, फिर 2009 और 2014 में भी वहां से जीत हासिल की। लेकिन 2019 में अमेठी में हार गए, हालांकि केरल के वायनाड से जीत गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर जीत हासिल की और रायबरेली को रख लिया। कांग्रेस पार्टी 2014 और 2019 में बहुत कम सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में 99 सीटों तक पहुंच गई। इसके बावजूद कई राज्य चुनावों में कांग्रेस को हार मिली। बीजेपी ने दावा किया है कि 2004 से अब तक राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस को 95 चुनावी हार मिल चुकी हैं, जैसे बिहार 2025 में, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी। 2025 में दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में भी पार्टी को झटका लगा। अब 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राहुल इन चुनावों में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं। वे जातिगत जनगणना, महंगाई और किसान मुद्दों पर बात करते हैं। लोगों का एक वर्ग कहता है कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को नई ऊर्जा दी। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस कई राज्यों में सत्ता से दूर है और राहुल को अब भी कई जगहों पर परिवारवाद का आरोप झेलना पड़ता है। यह सफर दिखाता है कि राहुल हारते जरूर हैं लेकिन मैदान छोड़ते नहीं।

समर्थकों की आवाज: बहादुरी की मिसाल बन राहुल

कई लोग राहुल गांधी की तारीफ इस बात के लिए करते हैं कि वे हार के बावजूद हिम्मत नहीं हारते। वे कहते हैं कि राहुल एक बहादुर नेता हैं जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 2019 की हार के बाद भी उन्होंने वायनाड से जीत हासिल की और 2024 में लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए। समर्थक मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल को आम लोगों के करीब लाया और उन्होंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी। वे जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे उठाते हैं जिसे सरकार ने 2025 में स्वीकार भी किया। राहुल संसद में सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो या विदेश नीति। एक बड़ा तबका उन्हें युवा और सच्चे नेता मानता है जो परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है लेकिन खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। लोग

चुनावी मैदान पर उतरते राहुल: जीत-हार का पूरा सफर



कहते हैं कि राहुल ने कभी हार मानकर इस्तीफा नहीं दिया बल्कि पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। तेलंगाना जैसे राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है और राहुल वहां दो साल के काम का जायजा ले रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि यह बहादुरी ही राहुल को अलग बनाती है क्योंकि भारतीय राजनीति में कई नेता छोटी-छोटी हार पर हार मान लेते हैं। लेकिन यह तारीफ तब और मजबूत होती है जब लोग देखते हैं कि राहुल गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए लगातार बोलते रहते हैं। यह सब दिखाता है कि उनका संघर्ष सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि विचारों के लिए भी है।

हकीकत का आईना: भारत जैसे देश की राजनीति में कितने फिट हैं राहुल?

हालांकि तारीफ के साथ-साथ सवाल भी उठते हैं कि राहुल गांधी भारत जैसे बड़े और जटिल देश की राजनीति के लिए कितने तैयार हैं। आलोचक कहते हैं कि राहुल ने कभी किसी राज्य की सरकार नहीं चलाई है, इसलिए प्रशासन का अनुभव उनकी कमी है। कई राज्य चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद लोग पूछते हैं कि क्या राहुल का नेतृत्व पार्टी को आगे ले जा रहा है या सिर्फ परिवार पर निर्भर है। 2025 के बिहार चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने उन्हें 95 हारों का जिक्र करके घेरा। आलोचना यह भी है कि राहुल कभी-कभी बयानों में विवाद में फंस जाते हैं और ठोस समाधान कम देते हैं। भारतीय राजनीति में स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय नेता और संगठन बहुत जरूरी हैं,

लेकिन कांग्रेस कई जगहों पर कमजोर दिखती है। राहुल की छवि कभी-कभी सिर्फ विपक्ष करने वाली बनी रह गई है बजाय नए रास्ते दिखाने के। फिर भी 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी हुई है जो दिखाता है कि राहुल की कुछ रणनीतियां काम कर रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या वे प्रधानमंत्री पद के लिए फिट हैं जहां फैसले लेने, गठबंधन बनाने और देश चलाने का अनुभव चाहिए। कई विश्लेषक मानते हैं कि राहुल में मेहनत है लेकिन व्यावहारिक राजनीति का अभ्यास कम है। यह सब सोचने पर लगता है कि भारत की राजनीति सिर्फ हिम्मत से नहीं चलती, बल्कि नतीजों से भी। राहुल को अब अपनी कमियों को स्वीकार करके और ज्यादा क्षेत्रीय नेताओं को आगे लाकर काम करना होगा।

आगे की राह: 2026 के चुनाव और उससे परे की संभावनाएं

2026 के विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण हैं। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में प्रचार चल रहा है जहां राहुल सक्रिय हैं। केरल में उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और छात्राओं के लिए मदद जैसे वादे किए हैं। तमिलनाडु और बंगाल में भी वे गठबंधन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन चुनावों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो राहुल की छवि मजबूत होगी। 2029 के लोकसभा चुनाव तक का समय है जहां वे विपक्ष के नेता के रूप

में और ज्यादा अनुभव हासिल कर सकते हैं। संभावना है कि अगर कांग्रेस राज्य स्तर पर सरकार बनाती है तो राहुल प्रशासनिक काम करके खुद को साबित करेंगे। लेकिन चुनौतियां भी हैं जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल और पुरानी हारों का असर। लोग सोचते हैं कि अगर राहुल अपनी रणनीति बदलें और ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर फोकस करें तो आगे बेहतर दिन आ सकते हैं। विपक्ष की एकता बनाए रखना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर 2026 के नतीजे तय करेंगे कि राहुल की यात्रा नई ऊंचाइयों पर जाती है या पुरानी चुनौतियां जारी रहती हैं। यह समय उनके लिए परीक्षा का है जहां हार न मानने की बहादुरी को असली नतीजों में बदलना होगा।

अंतिम सोच: संघर्ष जारी रहेगा या बदलाव आएगा?

राहुल गांधी की कहानी हार और हिम्मत दोनों की है। एक तरफ लोग उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं तो दूसरी तरफ सवाल उठते हैं कि क्या वे भारत की राजनीति के लिए पूरी तरह फिट हैं। हकीकत यह है कि भारतीय राजनीति में सिर्फ नाम या परिवार काफी नहीं, बल्कि नतीजे और अनुभव चाहिए। राहुल ने पिछले सालों में बहुत कुछ सीखा है लेकिन अभी भी कई जगहों पर सुधार की जरूरत है। आगे चलकर अगर वे क्षेत्रीय नेताओं को मौका दें, ठोस योजनाएं बनाएं और पार्टी को मजबूत करें तो संभावनाएं अच्छी हैं। 2026 के चुनाव इस दिशा में पहला कदम साबित हो सकते हैं। अंत में यह कहना सही होगा कि राहुल की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। वे संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष देश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब हार के बाद सीखकर आगे बढ़ें। यह सोच हमें यह सिखाती है कि राजनीति में धैर्य जरूरी है लेकिन नतीजे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

क्यों भारत में घरेलू कामगार सस्ते, लेकिन यूरोप में लक्जरी हैं?

नोएडा की ज़मीन से उठती एक कड़वी सच्चाई

@ आनंद मीणा

एक ही काम लेकिन दो दुनिया एक तरफ यूरोप और अमेरिका के शहर, जहां मेड या हाउसकीपर की नौकरी को लक्जरी माना जाता है। और दूसरी तरफ भारत, जहां यही काम करने वाले लोग आज भी बुनियादी सम्मान और अधिकार के लिए जूझ रहे हैं। यह फर्क सिर्फ पैसों का नहीं है यह सोच का फर्क है, सिस्टम का फर्क है, और सबसे बड़ा-इंसान को इंसान समझने का फर्क है।

यूरोप और अमेरिका में मेड एक प्रोफेशन, न कि नौकरी

अगर आप 2026 की रिपोर्ट्स देखें, तो न्यूयॉर्क जैसे शहरों में एक अनुभवी मेड सालाना \$70,000 से \$1,00,000 तक कमाती है। भारतीय रुपये में देखें तो ये करीब 60 से 85 लाख रुपये सालाना बैठता है। अब जरा सोचिए जिस काम को भारत में छोटा काम कहा जाता है, वही काम वहां एक सम्मानजनक करियर है। मेड को नौकर नहीं, बल्कि वर्कर कहा जाता है। ज्यादातर मेड अपनी कार से काम पर आती हैं, भले वो बेसिक या पुरानी कार हो। कई अमीर परिवार उन्हें कार अलाउंस या गैस के पैसे भी देते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में काम के घंटे तय होते हैं। 15 बजे के बाद काम करने पर ओवरटाइम देना जरूरी है। साल में 20 से 30 दिन की पेड लीव मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। राइट टू डिस्कनेक्ट होता है मतलब काम के बाद मालिक फोन नहीं कर सकता। मेड्स बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल के लिए उन्हें सर्टिफिकेट लेने होते हैं, जिससे उनकी सैलरी और बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात वहां डिमिटी ऑफ लेबर है। मेड मालिक के साथ एक ही टेबल पर खाना खा सकती है। उसे सूट-बूट या फॉर्मल कपड़ों में देखना वहां बिल्कुल सामान्य है।

भारत में मेहनत वही, इज्जत आधी

अब भारत की तरफ आइए। यहाँ लाखों घरेलू कामगार जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है, आज भी 10-11 हजार रुपये महीने पर काम कर रही हैं। कई जगहों पर यह रकम इससे भी कम है। 10 से 12 घंटे रोज ओवरटाइम? ज्यादातर मामलों में नहीं मिलता। यहां तक कि कुछ जगहों पर तो स्थिति इतनी खराब है कि काम के दौरान उन्हें अपनी जगह से उठने तक की इजाजत नहीं होती। यह वही समाज है जो सोशल मीडिया पर "पीरियड लीव" की मांग करता है लेकिन जब असली जिंदगी में महिला मजदूरों को basic राहत तक नहीं मिलती, तो वही समाज खामोश हो जाता है।

नोएडा जैसे शहर की सस्ती मजदूरी

अब जरा नोएडा की तस्वीर देखिए। नोएडा जहां ऊंची-ऊंची सोसाइटी, मॉल, और करोड़ों के फ्लैट हैं। लेकिन इन्हीं सोसाइटी के पीछे एक और दुनिया है। यहां कई घरेलू कामगार और मजदूर सिर्फ 300 रुपये रोज कमाते हैं। अब हिसाब लगाइए कि महीने की कमाई करीब 9,000 रुपये। किराया: 4,000-6,000 रुपये, राशन: 2,000-3,000 रुपये, बच्चों की पढ़ाई: अलग खर्च

न्यूयॉर्क में मेड की सालाना कमाई \$70,000-\$1,00,000 तक, जबकि भारत में 10-12 घंटे काम के बावजूद सिर्फ 10-11 हजार महीना; नोएडा जैसे शहर में कई मजदूर 300 रोज पर गुजारा करने को मजबूर।



न्यूयॉर्क में मेड 60-85 लाख सालाना, भारत में 10-11 हजार महीना
यूरोप में ओवरटाइम अनिवार्य, भारत में अक्सर बिना भुगतान काम
वहां वर्कर, यहां आज भी नौकर
नोएडा में 300 रोज पर चल रहा है पूरा परिवार

, दवाइयां: दिन-ब-दिन महंगी हो रही है। अब सवाल यह है इतने में कोई इंसान जिंदा कैसे रहता है?

यही असली कहानी है, जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। नोएडा जैसे शहर में, जहां एक कॉफी 300 रुपये की मिलती है, वहीं एक मजदूर की पूरे दिन की कमाई भी 300 रुपये है। यह सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं है यह एक सिस्टम की असफलता है।

पंसा नहीं, मानसिकता बड़ी दिक्कत है

अक्सर लोग कहते हैं कि भारत गरीब देश है, इसलिए मजदूरी कम है। लेकिन यह आधा सच है। असल समस्या हमारी सोच है। भारत में अभी भी एक सामंती यानी सामंती सोच गहराई से बैठी हुई है, जहां काम के आधार पर इंसान की इज्जत तय की जाती है। जो ऑफिस में बैठता है, वह सम्मानित जो झाड़ू-पोंछा करता है, वह नौकर।

यही सोच सबसे बड़ी दीवार है

यूरोप में लोग समझते हैं कि हर काम जरूरी है। इसलिए वहां काम छोटा-बड़ा नहीं, बल्कि काम होता है। भारत में हम अभी भी लोगों को उनके काम से जज करते हैं। यूरोप में हर चीज लिखित में होती है। कॉन्ट्रैक्ट, नियम, अधिकार-सब तय। भारत में? आप भरोसा रखिए और यही भरोसा अक्सर शोषण में बदल जाता है। घरेलू कामगारों के पास कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई तय छुट्टी नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई शिकायत सिस्टम नहीं। अगर काम छोड़ दें, तो तुरंत दूसरी मिल जाएगी-इस



डर से वो आवाज भी नहीं उठाते।

महिलाओं की दोहरी मार

घरेलू कामगारों में बड़ी संख्या महिलाओं की है। और उनके साथ समस्या दोगुनी है। कम वेतन, लंबा काम, घर की जिम्मेदारी अलग। कई महिलाएं सुबह 5 बजे उठती हैं, अपने घर का काम करती हैं, फिर 3-4 घंटों में काम करने जाती हैं, और रात तक काम करती रहती हैं। फिर भी उन्हें काम वाली बाई कहकर बुलाया जाता है। नाम तक नहीं। सम्मान क्यों जरूरी है? यह सिर्फ पैसे का मुद्दा नहीं है। सम्मान एक बुनियादी जरूरत है। जब आप किसी को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसका काम भी बेहतर होता है, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यूरोप में यही होता है। इसलिए वहां कामगार सिर्फ काम नहीं करते-वे प्रोफेशनल होते हैं।

भारत में अगर हम सिर्फ एक बदलाव कर दें लोगों

को इंसान की तरह देखना शुरू कर दें तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी।

क्या बदलाव संभव है?

घरेलू कामगारों के लिए लिखित एग्रीमेंट हो यानी तय काम के घंटे, ओवरटाइम का भुगतान, साप्ताहिक छुट्टी, हेल्थ सपोर्ट। और सबसे जरूरी-व्यवहार में बदलाव। हम अक्सर बड़े-बड़े मुद्दों पर बात करते हैं-इकोनॉमी, ग्रोथ, GDP लेकिन एक देश की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यूरोप में मेड लक्जरी है क्योंकि वहां लेबर महंगी है। भारत में मेड जरूरत है क्योंकि लेबर सस्ती है। लेकिन सवाल यह है-क्या हम हमेशा इसी सोच में रहना चाहते हैं? या फिर हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां हर काम को इज्जत मिले और हर इंसान को भी क्योंकि आखिर में काम नहीं, इंसान बड़ा होता है।

प्रश्नावली

जिसे आपके हाथों ने धामा न हो उसे जाने देने की प्रक्रिया क्या है?
अजन्मे सपने को कैसे दफ़नाते हैं?

पंक्तियों के बीच पढ़ने को कहा जाता है
पर उतनी-सी कोरी जगह में नई पंक्तियाँ लिखी कैसे जाएँ?

उन शब्दों को धैर्य से कैसे सुना जाए
जिन्हें इस क्रम में पहले कभी साथ लाया ही नहीं गया?

कोई पीड़ा लगातार शरीर में अपनी जगह बदले तो उसकी कैसी
चिकित्सा हो?
उस रास्ते से मोह कैसे जताया जाए जिधर कभी मुड़े नहीं, बस दूर से
देखा हो?

ठीला कैसे छोड़ें उस देह को जो बिना तनाव के जी ही न हो?
'साँस बाहर' की क्रिया कैसे करें जब इतनी देर से साँस धामे बैठे
थे कि अब वजह याद नहीं,

और फिर धामे रह गए कि कहीं बाद में याद आ जाए?
कोयल की हरीतिमा को सहलाया कैसे जाए जो उसका आकार मालूम
न हो?

ग्लोब इस ढंग से कैसे पकड़ें कि आपकी उँगलियों की छुआन से
कोई भी हिस्सा अछूता न रहे?
उन हाथों को गालों पर कैसे टिकाएँ ताकि किन्हीं अनछुई लकीरों
की स्मृति त्वचा को जला न दे?

कुछ औरतें

कुछ औरतें अपने बुने को उधेड़ देती थीं
कुछ चूल्हे के बुझ जाने पर देर तक

नज़र गड़ाए रखती थीं अंगारों में,
आँखों में उगाती थीं नसों के लाल पेड़

कुछ कुएँ से पानी निकालते हुए बहुत
ज़्यादा भीतर तक डूबने देती थीं बाल्टी को

आने देती थीं ऊपर जो भी आना चाहता था
कुछ घरवालों से छिपकर उस गाय को

गुड़ दे आती थीं जो फिर गाभिन नहीं होती,
और कुछ देर शांत बैठती थीं

उस दशहरे प्रसाद होने वाले पठरु 1 के साथ
कुछ रोज़ जाती थीं आत्मकामी या बेरुख़े पति की शैय्या
पर,

और सोती थीं रात के संग, अगले पहर जागती हुईं
कुछ बेटे को भी ओढ़नी बाँध खेलने देती थीं

और हाथ की सफ़ाई से टपका देती थीं
बेटी की थाली में घी

कुछ सुबह की चाय में देशी के लिए रोज़ उलाहने सुनतीं
और नहीं बताती किसी को कि सुबह नदी के लिए

जाते हुए वो आम के बगीचे में रुकी थीं,
न ये खुलासा करती कि क्या घटा दोनों के बीच

कुछ ने डरती सहेलियों के हाथ दबा
उनके इलज़ाम अपने सर ले लिए थे,

और उनके निशान भी
कुछ औरतें सालों पहले अन्य जाति के लड़के को देख
मुस्कराई थीं

और सालों बाद भी खुले दालान में सबके साथ बैठीं
उसे अंदर कहीं बंद रखती थीं सुरक्षित,

और इस जीत को सोचकर फिर से मुस्कराती थीं
क्योंकि कुछ औरतों को आता था

आने के साथ जाना भी,
उनसे सब डरने लगे

घोषित करने लगे उनके पाँवों को उल्टा
जब कहा कुछ औरतों ने कि वो कई मर्तबे

झुलसी हैं जिस इंसान के साथ सोने पर
अब उसकी चिता पर तो वो साथ नहीं लेटेंगी

तो होम किया गया उन्हें
और उस भभूत से बहुत रोती बहुत औरतों ने

रगड़ डाली कई कड़हियाँ
जब तक कुछ औरतों की शक्ल

नहीं झलक आई लोहे पर
और बहुत औरतों ने अंदर कहीं बंद रख लिया सुरक्षित

उन चेहरों को
और इस जीत को सोचकर फिर मुस्कराने लगीं।

अंकिता आनंद

नई पीढ़ी की कवयित्री। स्त्रीवादी विचारों के लिए उल्लेखनीय।

भारत की अर्थव्यवस्था छठे नंबर पर पहुंची: जीडीपी का खेल समझें या सिर्फ आंकड़े?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अप्रैल 2026 में जो नई रिपोर्ट जारी की है, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नाममात्र जीडीपी यानी डॉलर में कुल उत्पादन के हिसाब से भारत का आंकड़ा 2026 में करीब 4.15 ट्रिलियन डॉलर रहने वाला है। इससे पहले 2024 में भारत पांचवें स्थान पर था और कुछ समय के लिए चौथे पर भी पहुंच गया था। लेकिन अब अमेरिका सबसे आगे है जिसकी जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, उसके बाद चीन 19 ट्रिलियन के करीब, जर्मनी तीसरे स्थान पर, जापान चौथे पर 4.38 ट्रिलियन डॉलर के साथ और ब्रिटेन पांचवें पर 4.26 ट्रिलियन डॉलर के साथ। भारत इनके पीछे छठे नंबर पर आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ के अनुसार 2026 में भारत की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है जो जापान या ब्रिटेन से कहीं ज्यादा है। यह गिरावट असल में अर्थव्यवस्था के कमजोर होने की वजह से नहीं आई। बल्कि डॉलर में हिसाब लगाने के तरीके और कुछ आंकड़ों के बदलाव से हुई है। आम लोग सोचते हैं कि रैंकिंग गिरना बुरी खबर है लेकिन असल में देश की अंदरूनी गतिविधियां जैसे कारखाने चलना, सेवाएं बढ़ना और रोजगार बनना मजबूत बने हुए हैं। सिर्फ वैश्विक मुद्रा के खेल ने रैंकिंग को थोड़ा पीछे धकेल दिया। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रैंकिंग वाकई देश की ताकत बताती है या सिर्फ एक क्षणिक तस्वीर है। आम आदमी के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी घरेलू मांग, निवेश और निर्यात पर मजबूत आधार रखती है। भले ही डॉलर में आंकड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन रुपये में विकास जारी है।

रैंकिंग के पीछे की असली कहानी

दरअसल भारत की रैंकिंग छठे नंबर पर जाने की दो मुख्य वजहें हैं। पहली वजह भारतीय रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना है। 2024 में एक डॉलर के बदले करीब 84 रुपये थे जो 2025 में बढ़कर 88 रुपये से ज्यादा हो गए। जब हम अपनी जीडीपी को डॉलर में बदलते हैं तो कमजोर रुपये से कुल आंकड़ा छोटा हो जाता है। भले ही देश में उत्पादन बढ़ रहा हो। दूसरी वजह फरवरी 2026 में आधार वर्ष का बदलाव है। सरकार ने जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया। इससे नाममात्र जीडीपी का आंकड़ा थोड़ा कम हो गया। पुराना तरीका कुछ क्षेत्रों में ज्यादा अनुमान लगा रहा था इसलिए नया आधार ज्यादा सही और वास्तविक है। लेकिन इसका असर रैंकिंग पर पड़ा। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में भारत की जीडीपी 3.92 ट्रिलियन डॉलर रह गई जबकि जापान 4.44 ट्रिलियन और ब्रिटेन 4 ट्रिलियन के करीब रहा। फिर भी भारत की असल विकास दर 7.6 प्रतिशत रही जो बहुत अच्छी है। आम भाषा में समझें तो जैसे कोई दुकानदार अपनी कमाई रुपये में गिनता है लेकिन बाजार में डॉलर की तुलना करता है तो कमजोर रुपये से कमाई छोटी लगती है। वैसे ही देश

भारत की जीडीपी रैंकिंग में यह बदलाव क्यों आया?



की अर्थव्यवस्था भी वैश्विक मुद्रा में छोटी दिख रही है। लेकिन यह स्थायी नहीं है। आईएमएफ खुद कह रहा है कि 2027 तक भारत फिर चौथे स्थान पर पहुंच सकता है क्योंकि रुपये की स्थिति सुधर सकती है और विकास जारी रहेगा। यह हमें याद दिलाता है कि रैंकिंग सिर्फ एक पल की तस्वीर है न कि पूरी कहानी।

जापान और ब्रिटेन जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं स्थिर रहते हुए रैंकिंग क्यों बदलती हैं?

जापान और ब्रिटेन जैसी पुरानी और स्थिर अर्थव्यवस्थाएं भी रैंकिंग में ऊपर नीचे होती रहती हैं। वजह यही है कि नाममात्र जीडीपी डॉलर में मापी जाती है। अगर जापान का येन डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाए तो उसकी जीडीपी डॉलर में बढ़ जाती है भले ही देश में उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ा हो। ठीक वैसे ही ब्रिटेन का पाउंड अगर डॉलर के सामने थोड़ा मजबूत रहता है तो उसकी रैंकिंग ऊपर चली जाती है। 2025-26 में जापान की मुद्रा और ब्रिटेन की पाउंड ने बेहतर प्रदर्शन किया जिससे वे भारत से आगे निकल गए। लेकिन इन देशों की असल अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी उछाल नहीं आई। जापान तो पिछले कई सालों से बहुत धीमी वृद्धि कर रहा है फिर भी मुद्रा के खेल से रैंकिंग बनी रही। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी 0.8 प्रतिशत के आसपास बढ़ रही है जो भारत से बहुत कम है। फिर भी नाममात्र जीडीपी में वे आगे हैं। यह दिखाता है कि विकसित देशों की रैंकिंग भी मुद्रा विनिमय दर पर निर्भर करती है न कि सिर्फ उत्पादन पर। आम आदमी के लिए यह उदाहरण समझने लायक है कि जैसे कोई परिवार अपनी कमाई डॉलर में सोचे तो छोटा

लगे लेकिन घरेलू जरूरतें पूरी हो रही हों। जापान और ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है लेकिन कुल आंकड़े मुद्रा के कारण बदलते रहते हैं। इससे साफ होता है कि रैंकिंग अस्थिर होती है और सिर्फ एक साल के आंकड़े पर पूरा फैसला नहीं लेना चाहिए।

क्या सिर्फ जीडीपी से किसी देश की आर्थिक स्थिति का सही आकलन हो सकता है?

सिर्फ जीडीपी से देश की आर्थिक स्थिति का पूरा और सही आकलन नहीं किया जा सकता। जीडीपी बताता है कि कुल कितना सामान और सेवा बनी लेकिन यह कई महत्वपूर्ण बातों को छोड़ देता है। सबसे पहले जनसंख्या। भारत की आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए प्रति व्यक्ति जीडीपी बहुत कम है जबकि जापान या ब्रिटेन में कम आबादी होने से प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। दूसरा मुद्रा असमानता। अमीर और गरीब के बीच का फर्क बढ़ रहा हो तो कुल जीडीपी अच्छा दिखने पर भी आम आदमी की स्थिति सुधर नहीं रही। तीसरा गैर बाजारी काम जैसे घरेलू काम महिलाओं द्वारा किया जाना या पर्यावरण की रक्षा यह सब जीडीपी में नहीं गिने जाते। चौथा खरीद क्षमता समता यानी पीपीपी। पीपीपी में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है क्योंकि यहां चीजें सस्ती हैं और लोग ज्यादा खरीद पाते हैं। नाममात्र जीडीपी सिर्फ डॉलर एक्सचेंज पर आधारित है जो कभी-कभी गलत तस्वीर देता है। उदाहरण के लिए अगर रुपये में सब कुछ सस्ता है तो लोग ज्यादा खुश रह सकते हैं लेकिन डॉलर में आंकड़ा छोटा लगता है। इसके अलावा जीडीपी प्रदूषण या स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को नहीं गिनता। अगर कारखाने ज्यादा चले

और प्रदूषण बढ़े तो जीडीपी बढ़ता है लेकिन लोगों की सेहत खराब होती है। इसलिए कई विशेषज्ञ कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक या खुशी सूचकांक जैसे अन्य मापदंड भी देखने चाहिए। संतुलित नजरिए से जीडीपी एक अच्छा औजार है लेकिन अकेला नहीं। हमें प्रति व्यक्ति आय, रोजगार गुणवत्ता और पर्यावरण को भी साथ रखकर देखना चाहिए।

भारत की मजबूत विकास यात्रा और सच्ची तस्वीर

भविष्य की ओर देखें तो भारत की कहानी अभी भी आशा भरी है। आईएमएफ कह रहा है कि 2027 तक भारत फिर चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा जब उसकी जीडीपी 4.58 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। 2028 में जापान को भी पीछे छोड़ सकता है। असल ताकत भारत की युवा आबादी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सरकारी सुधारों में है। लेकिन हमें सिर्फ रैंकिंग पर नहीं रुकना चाहिए। सच्ची आर्थिक स्थिति तब सुधरेगी जब हर व्यक्ति को बेहतर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। जीडीपी बढ़ाने के साथ-साथ असमानता कम करना और पर्यावरण बचाना भी जरूरी है। विकसित देशों से सीख लें कि वे स्थिर रहकर भी रैंकिंग बनाए रखते हैं लेकिन भारत को अपनी ताकत यानी तेज विकास और बड़े बाजार पर भरोसा रखना चाहिए। आम नागरिक के लिए यह समझना जरूरी है कि रैंकिंग बदलती रहती है लेकिन देश की अंदरूनी मजबूती पर काम जारी रखें तो लंबे समय में फायदा होगा। सरकार, उद्योग और लोगों को मिलकर काम करना होगा ताकि विकास सबके लिए हो। अंत में जीडीपी एक नंबर है लेकिन सच्ची प्रगति लोगों की बेहतरी में है।

दुल्हनों को 8 ग्राम सोना देने का वादा: विजय की योजना और तमिलनाडु की सोने वाली लगन विजय का ऐलान: दुल्हनों को सोना और मासिक मदद

तमिलनाडु में अप्रैल 2026 के चुनाव को लेकर टीवीके पार्टी के नेता विजय ने हाल ही में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने महिलाओं के लिए कई अच्छे वादे किए हैं। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हर महिला को जो 60 साल से कम उम्र की है उसे हर महीने 2500 रुपये की मदद मिलेगी। साथ ही गरीब परिवारों की दुल्हनों को शादी के समय 8 ग्राम सोना और एक अच्छी सिल्क की साड़ी दी जाएगी। यह मदद उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है। विजय ने कहा कि यह भाई की तरह दुल्हन को तोहफा होगा। इसके अलावा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख तक का लोन और परिवारों को साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर भी देने का वादा है। यह घोषणा इसलिए खास है क्योंकि तमिलनाडु के चुनाव में महिलाएं बड़ी संख्या में वोट करती हैं। विजय जो पहले फिल्म अभिनेता थे अब राजनीति में हैं और वे जानते हैं कि सोना और पैसे की मदद से महिलाओं का दिल जीता जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि यह वादा शादी जैसे बड़े खर्च को थोड़ा कम कर सकता है। गरीब परिवारों में शादी का बोझ बहुत होता है और सोना देकर विजय ने उस पर ध्यान दिया है। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इतना खर्च सरकार कैसे उठाएगी। फिर भी यह योजना महिलाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम लग रही है। तमिलनाडु में पहले भी कई पार्टियां महिलाओं को मदद देती रही हैं लेकिन विजय ने इसे सोने से जोड़कर अलग बनाया है। अब देखना होगा कि अप्रैल 23 को होने वाले चुनाव में लोग इस पर कितना भरोसा करते हैं।

तमिलनाडु के घरों में अमेरिका जितना सोना

तमिलनाडु के कई घरों में सोना इतना है कि अगर उसे इकट्ठा किया जाए तो वह अमेरिका के सरकारी खजाने जितना बन जाता है। अनुमान है कि तमिलनाडु के घरों में करीब 6720 टन सोना रखा हुआ है। अमेरिका के पास सरकारी तौर पर 8133 टन सोना है यानी दोनों में बहुत कम फर्क है। पूरे भारत के घरों में 25000 से 34600 टन सोना है जो अमेरिका के खजाने से चार गुना ज्यादा है। दक्षिण भारत में ही भारत के कुल धरेलू सोने का 40 प्रतिशत हिस्सा है और तमिलनाडु उसमें सबसे आगे है। यह सोना ज्यादातर महिलाओं के गहनों में है जैसे हार, कंगन, झुमके और थाली। लोग इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभालकर रखते हैं। सोने की कीमत बढ़ने से इसका कुल मूल्य अब कई लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह भारत की जीडीपी से भी ज्यादा है। तमिलनाडु के गांवों और शहरों दोनों में हर घर में सोना मिलेगा। कोई अमीर है तो ज्यादा गहने रखता है कोई गरीब है तो कम लेकिन सोना जरूर होता है। यह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा भी है। अगर कोई मुसीबत आए तो सोना बेचकर काम चलाया जा सकता है। विश्व गोल्ड काउंसिल जैसी संस्थाएं भी कहती हैं कि भारत में धरेलू सोना बहुत बड़ा है और तमिलनाडु उसका बड़ा हिस्सा है। लोग इसे अमेरिकी खजाने से तुलना करते हैं क्योंकि दोनों लगभग बराबर हैं। लेकिन फर्क यह है कि अमेरिका का सोना सरकारी तिजोरी में बंद है जबकि तमिलनाडु का सोना आम घरों की अलमारियों और बैंकों के लॉकर में है। यह बात दिखाती है कि तमिलनाडु के लोग सोने को कितना महत्व देते हैं।



शादी के रीति-रिवाज में सोने की अहमियत

तमिलनाडु की शादियों में सोना बहुत जरूरी माना जाता है। दुल्हन के लिए थाली यानी मंगलसूत्र सोने का होता है। इसमें 8 ग्राम या उससे ज्यादा सोना लगता है। परिवार दुल्हन को हार, कंगन, बिछिया और कान की बालियां भी सोने की देते हैं। यह सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद माना जाता है। लोग मानते हैं कि सोना शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। पुराने समय में महिलाओं को संपत्ति नहीं मिलती थी इसलिए शादी में सोना उनकी अपनी सुरक्षा बन जाता था। इसे स्त्री धन कहते हैं जो पति की मौत या मुसीबत में काम आता है। आज भी तमिल परिवार शादी में सोना देने को अपना फर्ज समझते हैं। गरीब परिवार भी कोशिश करते हैं कि कम से कम थाली का सोना तो हो। विजय का 8 ग्राम सोना देने का वादा इसी परंपरा को समझकर किया गया है। शादी में सोना न हो तो लोग इसे अपशकुन मानते हैं। दक्षिण भारत में सोने के गहने रोज भी पहने जाते हैं। बच्ची पैदा हो तो कान में सोने की बाली डाली जाती है। शादी के समय दुल्हन के पूरे परिवार की इज्जत सोने की मात्रा से जुड़ी होती है। लेकिन यह महंगा भी पड़ता है। एक औसत शादी में सोने पर लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। यही वजह है कि विजय जैसे नेता इस पर वादा करके लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सोना न सिर्फ सुंदर लगता है बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी संपत्ति छोड़ता है। तमिल संस्कृति में सोना और शादी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।

क्यों है तमिलनाडु में सोने का इतना प्यार

तमिलनाडु में सोने का प्यार बहुत पुराना है। संस्कृति में सोना लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी घर में खुशहाली लाती है। प्राचीन तमिल साहित्य जैसे सिलपदिकारम में भी सोने के गहनों का जिक्र है। लोग सोने को निवेश समझते हैं क्योंकि इसकी कीमत कभी गिरती नहीं बल्कि बढ़ती है। महंगाई के समय सोना सबसे सुरक्षित बचत है। दक्षिण भारत में आमदनी अच्छी है इसलिए लोग सोना



खरीद सकते हैं। तमिलनाडु सोने के गहनों का बड़ा बाजार भी है। यहां के ज्वेलर्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। महिलाएं रोज सोने के गहने पहनती हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ी तक हर किसी के पास कुछ न कुछ सोना होता है। यह दीवानगी सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि परिवार की परंपरा है। पिता बेटे की शादी में सोना देकर उसे सुरक्षित भविष्य देते हैं। कई परिवारों में मां की शादी का सोना बेटे को मिलता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी सोना अच्छा है क्योंकि इसे आसानी से बेचा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पुरानी सोच है लेकिन ज्यादातर तमिल लोग इसे अपनी पहचान मानते हैं। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण में सोने की खपत ज्यादा है। तमिलनाडु अकेला 28 प्रतिशत धरेलू सोना रखता है। यह प्यार पीढ़ियों से चला आ रहा है और चुनाव में नेता इसे भुनाते हैं। विजय का वादा इसी लगन को समझकर है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इतना सोना रखना कभी-कभी बेकार पैसा फंसाना भी है। फिर भी लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि यह भावनाओं से जुड़ा है।

यह वादा कितना असरदार साबित होगा

विजय का 8 ग्राम सोना देने का वादा तमिलनाडु की संस्कृति को छूता है लेकिन इसे लागू करना आसान

नहीं होगा। एक तरफ तो गरीब दुल्हनों को मदद मिलेगी जिससे शादी का बोझ कम होगा। महिलाएं खुद को मजबूत महसूस करेंगी। दूसरी तरफ सरकार पर खर्च बढ़ेगा। अगर लाखों शादियां होती हैं तो सोने का कुल खर्च करोड़ों में पहुंच जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह वादा सिर्फ वोट के लिए है क्योंकि पहले भी ऐसे वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं हुए। फिर भी तमिलनाडु के लोग सोने को बहुत महत्व देते हैं इसलिए यह योजना उन्हें अच्छी लग रही है। राजनीति में महिलाओं को लक्ष्य करना सही रणनीति है क्योंकि वे परिवार की रीढ़ होती हैं। अगर विजय सत्ता में आए तो यह देखना होगा कि सोना कैसे और कब दिया जाएगा। क्या हर दुल्हन को मिलेगा या सिर्फ गरीबों को। इस वादे से सोने की मांग बढ़ सकती है जो स्थानीय ज्वेलर्स के लिए अच्छा है। लेकिन संतुलित नजरिए से देखें तो सोना सिर्फ तोहफा नहीं बल्कि सांस्कृतिक जरूरत भी है। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां घरों में पहले से इतना सोना है वहां यह वादा लोगों को और ज्यादा जोड़ सकता है। अंत में चुनाव तय करेंगे कि लोग इस पर भरोसा करते हैं या नहीं। यह वादा सोचने पर मजबूर करता है कि क्या संस्कृति और राजनीति एक दूसरे को कितना प्रभावित करते हैं।

क्यों IPL का हर चौका-छक्का पर्यावरण पर भारी पड़ रहा है?

@ मनीष पांडेय

जब भी IPL का सीजन आता है तो कोई विराट को सपोर्ट कर रहा होता है या कोई रोहित शर्मा के पीछे खड़ा होता है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक त्योहार जैसा हो चुका है। लेकिन इसी जश्न के पीछे एक सच्चाई भी है, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। सवाल यह नहीं है कि IPL अच्छा है या बुरा। सवाल यह है कि इस पूरे आयोजन की कीमत कौन चुका रहा है? और जवाब है हमारा पर्यावरण।

एक मैच से हजारों टन कार्बन निकल रहा है

आपने कभी सोचा है कि एक IPL मैच से कितना प्रदूषण होता है? आंकड़े बताते हैं कि एक मैच से लगभग 10,000 से 14,000 टन तक CO उत्सर्जन होता है। अब इसे पूरे सीजन के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा 750,000 से 900,000 टन तक पहुंच जाता है। इसे समझने के लिए एक आसान तुलना करें तो यह लगभग 2 लाख कारों के एक साल के उत्सर्जन के बराबर है। यानी जितना प्रदूषण लाखों गाड़ियां पूरे साल में करती हैं, उतना IPL कुछ हफ्तों में कर देता है। अब सवाल उठता है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? इसके लिए अनुमान है कि लगभग 4 करोड़ पेड़ों को एक साल तक विकसित करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ संतुलन बन पाएगा। सोचिए, सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए इतनी बड़ी कीमत।

स्टेडियम की रोशनी बुझा रही है पर्यावरण को

क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ मैच के दिन ही नहीं चलते, उन्हें रोज व्यवस्थित करना पड़ता है। इसके लिए रोजाना 15,000 से 20,000 लीटर पानी की जरूरत होती है।

अगर हफ्ते का हिसाब देखें, तो एक स्टेडियम को 270,000 लीटर से ज्यादा पानी चाहिए होता है। ऐसे में जब कई शहर पहले से पानी की कमी झेल रहे हैं, यह आंकड़ा चिंता बढ़ाता है। बिजली की बात करें तो सिर्फ चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही हर साल लगभग 1.6 लाख यूनिट बिजली खर्च होती है, जिस पर करीब 1,33,34,904 का खर्च आता है। और यह सिर्फ एक स्टेडियम का आंकड़ा है। पूरे देश के सभी IPL स्टेडियम मिलाकर सोचिए, यह खर्च और खपत कितनी बड़ी होगी।

मैच के बाद लद जाता है कचरे का पहाड़

मैच खत्म होते ही जो चीज सबसे ज्यादा बचती है, वह है कचरा। फूड पैकेजिंग, सिंगल-यूज प्लास्टिक बोटलें, फैन मर्चेन्डाइज सब मिलकर एक बड़ा कचरे का ढेर बना देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, एक मैच से लगभग 48,000 किलो कचरा निकलता है। यानी सिर्फ एक रात के मनोरंजन के लिए टनों कचरा पैदा हो जाता है। यह कचरा सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रहता। इसका असर आसपास के इलाकों, नालियों और आखिर में हमारी नदियों और जमीन पर पड़ता है।

एक IPL मैच से 10,000—14,000 टन CO उत्सर्जन होता है, जबकि पूरे सीजन में यह 7.5 से 9 लाख टन तक पहुंच जाता है, जो लगभग 2 लाख कारों के सालभर के प्रदूषण के बराबर है

एक मैच से 48,000 किलो कचरा, जश्न के बाद कचरे का पहाड़

एक स्टेडियम को हर हफ्ते 2.7 लाख लीटर पानी, पिच हरी, शहर ज्यसा

1.6 लाख यूनिट बिजली सिर्फ एक स्टेडियम में।

नुकसान की भरपाई के लिए 4 करोड़ पेड़-एक सीजन, कई सालों का बोझ



क्या हम जिम्मेदार हैं?

यहां एक बात साफ कर लेना जरूरी है—कोई यह नहीं कह रहा कि आप IPL देखना बंद कर दें। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग ऐसा करेंगे भी नहीं। क्रिकेट हमारे देश की भावना से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम आंखें बंद कर लें। अगर हम इस खेल को इतना प्यार करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी।

उम्मीद की किरण भी है

अच्छी बात यह है कि कुछ कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। बसीसीआई ने एक पहल शुरू की है, जिसमें हर डॉट बॉल पर 500 पौधे लगाने की बात कही गई है। इसी तरह रॉयल चैलेंजर बंगलुरु के खिलाड़ी और स्टाफ जो टी-शर्ट पहनते हैं, वह से बनी होती हैं। यह छोटे कदम हैं, लेकिन सही दिशा में हैं। अगर बाकी टीमों भी ऐसे कदम उठाएं और फैंस भी इस मुद्दे को गंभीरता से लें, तो हालात में बदलाव आ सकता है।

असली बदलाव कहां से आएगा?

बदलाव सिर्फ बड़े संगठनों से नहीं आता, वह लोगों

से आता है। अगर फैंस चाहें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। स्टेडियम में सिंगल-यूज प्लास्टिक का कम इस्तेमाल। पानी और बिजली की बचत को लेकर जागरूकता। कचरे को सही तरीके से डिस्पोज करना और सब से

जरूरी, इस मुद्दे पर बात करना। जब लोग सवाल पूछेंगे, तभी सिस्टम बदलेगा।

जश्न मनाइए, लेकिन समझदारी के साथ

IPL एक त्योहार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर त्योहार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम सिर्फ जश्न मनाते रहेंगे और उसके असर को नजरअंदाज करेंगे, तो धीरे-धीरे यह नुकसान इतना बढ़ा हो जाएगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम आज से ही थोड़ा सोचें, थोड़ा समझें और छोटे-छोटे कदम उठाएं, तो इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्रिकेट हमें जोड़ता है, खुशी देता है, यादें बनाता है। लेकिन यह खुशी अगर प्रकृति की कीमत पर आ रही है, तो थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। आप मैच देखिए, अपने पसंदीदा खिलाड़ी को सपोर्ट कीजिए, जश्न मनाइए, लेकिन साथ ही यह भी समझिए कि इसके पीछे क्या हो रहा है। क्योंकि जब हम समझेंगे, तभी बदलाव आएगा। और शायद तब हम कह पाएंगे कि हमने सिर्फ खेल का आनंद ही नहीं लिया, बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ जिया भी है।





प्रभु कृपा दुख निवारण समागम

BY

**Arihanta
Industries**

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML



**ULTIMATE
HAIR
SOLUTION**

NO

ARTIFICIAL
COLOR
FRAGRANCE
CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.



ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in

Arihanta Industries